घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 228- शुक्रवार 19- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

टेलीग्राम पर सख्ती से मचा बवाल

अब केंद्र सरकार ने कहा...आतंकी गतिविधियों का अड्डा बना टेलीग्राम

नई दिल्ली,18 जून 2026। भारत सरकार ने हाल ही में सिक्योर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को हफ्ते भर के लिए बैन कर दिया है। टेलीग्राम ने कोर्ट में चैलेंज भी किया है। टेलीग्राम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि टेलीग्राम आतंकवादी गतिविधियों के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बन गया है। मामले की सुनवाई से पहले सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि इस केस में विस्तृत जवाब कोर्ट रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया गया है। जैसे ही यह रिकॉर्ड पर आएगा, सुनवाई शुरू होगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि टेलीग्राम को बुलाया गया था और उनकी बात सुनी गई। उनकी दलीलों और उस पर की गई जांच के निष्कर्ष रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की सुनवाई एक कमेटी ने की थी, जिसकी अगुवाई कैबिनेट सचिव ने की। इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 48 घंटे के अंदर सुनवाई का मौका देना जरूरी होता है। इस पर सरकार ने कहा कि इस मामले में सुनवाई का अवसर दिया गया था। अब इस केस में कोर्ट का अगला कदम अहम होगा, क्योंकि यह फैसला तय करेगा कि भारत में टेलीग्राम का भविष्य क्या होगा।

जंतर-मंतर पर फिर से प्रदर्शन की तैयारी में कॉकरोच जनता पार्टी

दिल्ली पुलिस से मांगी परमिशन

नई दिल्ली,18 जून 2026। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न होने से नाराज कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून को फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी गई है। बता दें कि नीट पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की थी कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में जारी रहेगा। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। अब उसी घोषणा को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांग रही है। बता दें कि 6 जून को हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुंग भी पहुंचे थे। इस दौरान सोनम वांगचुंग ने मंच से प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं सद्भावना और शांति का संदेश लेकर आया हूं। आप सब लोगों ने शांति पूर्वक प्रदर्शन का यह तरीका चुना है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शिकायत का यह मुद्दा आपने चुना है। यह प्रदर्शन नहीं आग्रह करने आये हैं। आगे भी हमें उम्मीद है सरकार सकारात्मक काम करेगी। इस्तीफे की बात हो रही है। लेकिन जिम्मेदारी की बात हो। सरकार के निर्णय से हम खुश हैं क्योंकि लोग कहते थे ऐसा होने नहीं देंगे। एजुकेशन का सवाल उठाया है तो क्यों न उठाएं। हमें उम्मीद है कि सरकार सही कदम उठाएगी। आने वाले दिनों में जो हम मांग कर रहे हैं पूरा हो। आगे इसे कैसे लेकर जाना है इस पर चर्चा करेंगे।

संजय राउत ने फिर अपमानजनक टिप्पणी की

नई दिल्ली,18 जून 2026। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज संसदीय दल की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पार्टी सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी जारी रखी। शिवसेना में संभावित फूट की अटकलों के बीच, पार्टी की संसदीय बैठक के लिए गुरुवार दोपहर तक सिर्फ तीन लोकसभा सांसद ही पहुंचे, जबकि सदस्यों को सुबह 11 बजे की बैठक के बारे में जानकारी दी गई थी। बागी खेमे में माने जाने वाले किसी भी सांसद ने अब तक बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। राज्यसभा सांसद और पार्टी के सीनियर नेता संजय राउत के अलावा, लोकसभा सांसद अनिल देसाई,अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे मीटिंग के लिए पहुंचे। इस बीच,संजय राउत ने संसद परिसर में पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो आएंगे वो हमारे और जो नहीं आएंगे, वो बेईमान और गद्दार हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट में संभावित दलबदल की अटकलों के बीच, शिवसेना के नेता संजय राउत,अरविंद सावंत और राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे गुरुवार को पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे। इस बैठक पर बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि पार्टी के संसदीय खेमे में संभावित फूट की खबरें लगातार आ रही हैं।

दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है भारत नाम, आईआईटी दिल्ली फिर बना देश का नंबर-1 इंस्टिट्यूट

नई दिल्ली,18 जून 2026। दुनिया की प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी कर दी गई है। इस बार भी भारत के लिए अच्छी खबर आई है। आईआईटी दिल्ली ने लगातार दूसरे साल देश के सबसे बेहतर शैक्षणिक और शोध संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी है। संस्थान ने इस बार वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक हासिल की है, जो किसी भारतीय संस्थान द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंकिंग की बराबरी है। अमेरिका की Massachusetts Institute of Technology ने लगातार 15वें साल दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी का स्थान बरकरार रखा है। यह रैंकिंग विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता, रिसर्च, वैश्विक प्रतिष्ठा और छात्रों के रोजगार जैसे मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। आईआईटी दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रगति की है। वर्ष 2024 में इसकी रैंकिंग 197वीं थी, जो 2025 में 150 वीं और अब 2027 में 118वीं हो गई है। यानी चार साल में संस्थान ने 79 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई है। संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि नए पाठ्यक्रम,आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कारण यह सफलता मिली है। आईआईटी दिल्ली को सबसे ज्यादा फायदा 'एम्प्लॉयर रेपुटेशन' और'एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स' श्रेणियों में मिला है।

भारत और यूरोप के बीच फ्रांस पुल जैसा : पीएम मोदी

एफिल टॉवर पर भी भारत का यूपीआई काम करता है,हमारे पास वर्ल्ड-क्लास डिजिटल पब्लिक गुड्स

नई दिल्ली,18 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार फ्रांस के पेरिस में आयोजित विवाटेक समिट में शामिल हुए। मोदी ने कहा...फ्रांस एक अहम पुल का काम कर रहा है जो भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब ला रहा है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की वजह से आज दुनिया के आधे रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। अब आप फ्रांस में भी एफिल टॉवर या पेरिस एयरपोर्ट पर यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई वर्ल्ड-क्लास डिजिटल पब्लिक गुड्स के उदाहरण हैं। डिजिलॉकर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट में से एक है। 17 जून को फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित ज7 समिट के बाद पीएम मोदी देर रात करीब 2 बजे पेरिस पहुंचे थे। यहां होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया था।

भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम : पिछले दशक में, भारत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म तक,हम फाइनेंशियल इन्क्लूजन, शिक्षा,टेलीमेडिसिन,खेती और कई अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'अंतरिक्ष तकनीक से लेकर नाभिकीय ऊर्जा तक,हम इंसानी क्षमता की सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना और हाल ही में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकैलिटी हासिल की। इसने हमें हमारे तीन-चरण वाले न्यूक्लियर विजन को साकार करने के करीब पहुँचाया है, जिसमें हमारे विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल भी शामिल है।

2026 भारत और यूरोप के लिए एक खास साल है : मोदी

साल की शुरुआत में,हमने ऐतिहासिक भारत-यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया। यह एग्रीमेंट हमारे व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा। इस साल 'भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर' की शुरुआत के साथ, फ्रांस एक अहम पुल का काम कर रहा है जो भारत और यूरोप के टेक इकोसिस्टम को करीब ला रहा है।

भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल : मोदी

भारत एक खुला समाज है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। हम नियमों को आसान बना रहे हैं और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुनिश्चित कर रहे हैं। इनोवेशन से लेकर कमर्शियलाइजेशन तक, हम 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा के खास इंसेंटिव के जरिए प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं।

भारत में दुनिया में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है : मोदी

हम दुनिया का सबसे सस्ता डेटा और कम लागत वाली ग्रीन एनर्जी भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नजरिया साफ है। हमारी सरकार सुविधा देगी और इंडस्ट्री इनोवेशन करेगी। स्टार्टअप्स बड़े बदलाव लाएंगे और ग्लोबल पार्टनर हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।

यूरोप का बड़ा तकनीकी सम्मेलन है विवाटेक : मोदी

विवाटेक यूरोप का बड़ा तकनीकी सम्मेलन है,जहां दुनियाभर की नई इंडस्ट्रीज,टेक्निक कंपनियां,इंवेस्टर और एक्सपर्ट नई टेक्निक और इनोवेशन का डिस्प्ले करते हैं। मुख्य तौर पर आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस,स्टार्टअप और उद्यमिता, डिजिटल प्रौद्योगिकी,साइबर सुरक्षा,हरित प्रौद्योगिकी,रोबोटिक्स, भविष्य की उभरती तकनीकों पर उन पर चर्चा करते हैं। यहां भारत का राष्ट्रीय मंडप (इंडिया पैवेलियन) भी स्थापित किया गया है,जहां देश के स्टार्टअप और तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

राम मंदिर चंदा विवाद के बीच सीएम योगी का आज

अयोध्या दौरा...चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रहने का निर्देश

नई दिल्ली,18 जून 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज को अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके इस प्रस्तावित कार्यक्रम में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन-पूजन सबसे प्रमुख है। मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले जारी हुए सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल निर्देशों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल के बिंदु संख्या 29 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने उनसे अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री के मंदिर भ्रमण की व्यवस्था के लिए वे किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करें और इसकी सूचना संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तुरंत दें।

विवादों के साये में प्रोटोकॉल का नया निर्देश

यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान पात्रों से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला सुर्खियों में है। हालांकि प्रशासन या ट्रस्ट की ओर से इस निर्णय के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इसे चंपत राय की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंदिर परिसर में चल रही जांच और चढ़ावे को लेकर मचे विवाद के बीच मुख्यमंत्री की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। चंपत राय की ओर से दी गई सफाई के बावजूद, प्रशासन का यह रुख कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है।

दान पात्रों के मामले में गठित एसआईटी की गहन जांच : अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों में चोरी और चढ़ावे के संबंध में लगाए जा रहे गंभीर आरोपों के बाद योगी सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया था। इस जांच दल में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस. और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार को शामिल किया गया है। ट्रस्ट का मानना है कि इस जांच से मंदिर के प्रबंधन पर लग रहे अफवाहों पर विराम लगेगा और दूध का दूध-पानी का पानी हो जाएगा।

जांच और प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री के दौरे पर सबकी नजरें

मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां एक ओर मंदिर ट्रस्ट मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी जांच पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान महासचिव को दूर रखने का निर्देश ट्रस्ट की आंतरिक स्थितियों को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म कर रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से यह कदम मुख्यमंत्री की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के अनुपालन का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी का इस महत्वपूर्ण दर्शन कार्यक्रम से अलग होना राज्य के राजनीतिक एवं धार्मिक हलकों में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।

हिमाचल के चंबा में सड़क हादसा...

गहरी खाई में गिरी बोलेरो,7 की मौत

चंबा,18 जून 2026। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बुधवार रात एक भयानक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। मुंडन संस्कार से लौट रहे परिवार के सदस्यों को ले जा रही बोलेरो गाड़ी पुखरी-मसरूंड मार्ग पर अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मुंडन संस्कार से लौटते समय हुआ हादसा

महल गांव के रहने वाले लोग काकड़ोथा गांव में मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे। वापसी के दौरान बोलेरो गाड़ी छतरूंड के पास अचानक बेकाबू हो गई और सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और खाई से शवों को बाहर निकाला।

7 लोगों की दर्दनाक मौत

इस दुर्घटना में 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों में तीन सगे भाई भी शामिल हैं, जिससे पूरे गांव में मातम का माहौल है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी शवों को खाई से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय निवासियों ने घटना के बाद गुस्सा जताते हुए कहा कि सड़क पर क्रैश बैरियर नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। उनका आरोप है कि अगर सुरक्षा दीवार लगी होती तो गाड़ी खाई में नहीं गिरती और कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।

तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके का विरोध प्रदर्शन,महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम विजय के खिलाफ की नारेबाजी

नई दिल्ली,18 जून 2026। तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के विधायकों ने विधानसभा में काले बैज पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य में युवतियों के खिलाफ बढ़ रही यौन हिंसा की घटनाओं को लेकर किया गया। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायक परिसर में एकत्र हुए और मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने'मुख्यमंत्री बोलिए', 'क्या आपको पीड़ितों की आवाज सुनाई दे रही है?' जैसे नारे लिखे पोस्टर भी दिखाए। डीएमके का आरोप है कि राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए उन्होंने यह विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार पर विपक्ष को कमजोर करने और राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे दलों के नेताओं व विधायकों को अपने साथ मिलाने का आरोप लगाया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सरकार की आलोचना करते हुए उसे 'सोफा मॉडल सरकार' बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। उनके अनुसार, कई लोग अब अपने मतदान के फैसले पर पछता रहे हैं।

शिवसेना यूबीटी में बड़ी टूट : व्हिप के बाद भी नहीं आए 6 लोकसभा सांसद,उद्धव गुट ने थमाया नोटिस,सदस्यता रद्द कराने की तैयारी

नई दिल्ली,18 जून 2026। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। साल 2022 में हुई शिवसेना की ऐतिहासिक टूट की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। दिल्ली में शिवसेना उद्धव गुट यानी शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय दल की एक बेहद जरूरी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद इस बैठक से गायब रहे। गायब होने वाले सांसदों की यह संख्या कुल ताकत का दो-तिहाई हिस्सा है। इस खुली बगावत को देखते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है और सभी अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

क्या दोबारा होने वाला है ऑपरेशन टाइगर : महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक हलकों में ऐसी अटकलें तेज हैं कि उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली शिवसेना के लगातार संपर्क में हैं और जल्द ही पाला बदल सकते हैं। इसी संभावित खतरे को भांपते हुए पार्टी ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली स्थित संसद कार्यालय में मौजूद रहने के लिए थ्री-लाइन व्हिप यानी एक बेहद सख्त सरकारी निर्देश जारी किया था। इसके बावजूद बैठक में सिर्फ तीन लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, राजभाऊ वाजे और अनिल देसाई ही पहुंचे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद संजय राउत भी वहां मौजूद थे।

यह गद्दारी और सोची-समझी साजिश है : बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए फायरब्रांड नेता संजय राउत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने बागी सांसदों के इस कदम को सीधे तौर पर धोखा, बेईमानी और सोची-समझी साजिश करार दिया। राउत ने कहा कि जो भी सांसद इस बैठक में नहीं आए हैं, उन्होंने पार्टी के आदेश का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि ये बागी सांसद कल लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर से मिलकर शिंदे गुट में विलय की मांग कर रहे थे। राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन लोगों ने उद्धव ठाकरे के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीत हासिल की है, इसलिए व्हिप का उल्लंघन करने पर इन्हें कानूनी तौर पर अयोग्य घोषित कराया जाएगा।

बागी सांसदों को थमाया गया कारण बताओ नोटिस : पार्टी के वरिष्ठ सांसद अनिल देसाई ने साफ किया है कि अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। बैठक खत्म होते ही गायब रहने वाले सभी छह सांसदों को फोन और व्हाट्सएप के जरिए कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। उनसे पूछा गया है कि संदेश मिलने के बाद भी वे बैठक में क्यों नहीं आए। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गंदी राजनीति की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी।

ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका,ऋतब्रता बनर्जी बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष

कोलकाता,18 जून 2026। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता हाई कोर्ट से गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को झटका लगा है। कोर्ट ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने टीएमसी के निष्कासित विधायक ऋतब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। कोर्ट के फैसले के बाद ऋतब्रता फिलहाल नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ममता के सहयोगी और टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिलता,इसलिए अंतरिम आदेश अस्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 3 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद टीएमसी आंतरिक विभाजन से जूझ रही है। बंगाल चुनाव में भाजपा ने 200 से अधिक सीटें और टीएमसी ने 80 सीटें जीती थी। इसके बाद ममता ने 6 मई को विधायकों की बैठक कर शोभनदेब को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। बाद में इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी गई। तभी 58 विधायकों के साथ ऋतब्रता बनर्जी ने बगावत कर ली और उनके सहयोग से खुद को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता दे दी। शोभनदेब इसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे।

पंचायत के मुखिया पर दिनदहाड़े फायरिंग,बाल-बाल बचे,ग्रामीणों ने घेरा थाना

गोड्डा,18 जून 2026। झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में गुरुवार को पंचायत मुखिया अनुपम भगत उर्फ लड्डू पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हमले में मुखिया बाल-बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पोड़ैयाहाट थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के अनुसार, अनुपम भगत स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक शाखा से लौट रहे थे। इसी दौरान मुख्य बाजार स्थित पंडित टोला कांबली बगीचा के पास उन पर फायरिंग की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो राउंड गोली चलाई गई।

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे नरेश गुजराल साइबर ठगी का शिकार,देश में हड़कंप

नई दिल्ली,18 जून 2026। देश की राजधानी दिल्ली में साइबर अपराध का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया है। अज्ञात ठगों ने नरेश गुजराल की फोटो का इस्तेमाल कर उनके ही एक भरोसेमंद कर्मचारी को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा और खुद को नरेश गुजराल बताकर बातचीत की। जालसाज ने कर्मचारी को यह विश्वास दिलाया कि वह एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, जिसके चलते वे सीधे बात नहीं कर सकते। इस झांसे में आकर कर्मचारी ने आरटीजीएस के जरिए ठगों द्वारा बताए गए बैंक खातों में बड़ी धनराशि ट्रांसफर कर दी। साइबर ठगों ने सुनियोजित तरीके से नरेश गुजराल की फाइनेंस टीम के उस सदस्य को निशाना बनाया,जिस पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा था। व्हाट्सएप पर फर्जी संदेश मिलने के बाद कर्मचारी ने बिना किसी संदेह के 12 जून से 16 जून के बीच चार किस्तों में कुल 7.8 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इतने बड़े स्तर पर हुई धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब इस लेनदेन की जानकारी नरेश गुजराल की बेटी दीक्षा को मिली।

संपादकीय

संकट में क्षेत्रीय दल

तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना-उद्धव गुट के नौ में से छह लोकसभा सदस्यों की ओर से शिवसेना-शिंदे में शामिल होने की तैयारी केवल यही नहीं बताती कि वे सत्तापक्ष के साथ जाने को आतुर हैं,बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि भारतीय राजनीति में मौकापरस्ती बढ़ती जा रही है। शिवसेना में यह दूसरी टूट है।

इसके पहले भी उसके विधायक एवं सांसद टूट चुके हैं और पार्टी अपना चुनाव चिह्न भी गंवा चुकी है। उसके लिए इस एक और झटके से उबर पाना कठिन होगा। अब उसके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। अपने इस संकट और बिखराव के लिए वही अधिक जिम्मेदार है। यदि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लालच में धुर विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ नहीं मिलाते तो शायद आज उनके दल की स्थिति कुछ और होती।

उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए अपनी पुरानी साझीदार और वैचारिक रूप से करीबी भाजपा से केवल नाता ही नहीं तोड़ा,बल्कि इसी के साथ अपनी विचारधारा को भी ताख पर रख दिया। शिवसेना उन कुछ क्षेत्रीय दलों में से थी, जिसकी अपनी एक विचारधारा थी। वह मूलतः अपनी विचारधारा से भटकने के कारण ही बिखरी।

तृणमूल कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं थी। केवल सत्ता पाना और उसमें येन-केन-प्रकारेण बने रहना ही उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु था। यह केंद्र बिंदु हटते यानी सत्ता जाते ही वह बिखर गई। क्षेत्रीय दलों की समस्या केवल यही नहीं कि उनमें से कुछ की ही विचारधारा है। एक समस्या यह भी है कि वे अलोकतांत्रिक तरीके और किसी निजी कंपनी की तरह चलते हैं। ऐसे दलों में पार्टी प्रमुख या परिवार विशेष ही सब कुछ होता है।

उसके आगे किसी की नहीं चलती। लोकतंत्र में अधिनायकवादी तरीके से चलने वाले दलों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए,लेकिन अपने देश की राजनीति का दुर्भाग्य यह है कि अनेक दल इसी तरह चलते हैं। प्रायः यही उनके बिखराव का कारण बनता है। क्षेत्रीय दलों में बिखराव का संकट इसलिए और बढ़ गया है, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधियों के लिए राजनीति का मतलब अवसरवाद हो गया है। वे कभी भी दल बदल लेते हैं। ज्यादातर मौकों पर पद या पैसे के लालच अथवा अन्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए दलबदल किया जाता है।

किसी के दल बदलने में हर्ज नहीं,लेकिन ऐसा करने के पहले यह आवश्यक है कि वे विधायक या सांसद पद से त्यागपत्र दें। ऐसा न करना जनादेश का निरादर है। लगभग सभी राजनीतिक दल समय-समय पर दलबदल को बढ़ावा देते रहे हैं। दलबदल रोधी कानून के बावजूद विधायकों-सांसदों के टूट का सिलसिला कायम है। हालांकि इस कानून को कठोर बनाया जा चुका है, लेकिन वह भी प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अब दलबदल को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता।

डांसिंग गर्ल : जिसे ढककर हम खुद को उजागर कर बैठे

प्रो.आर.के.जैन' अरिजीत'
बड़वानी मध्यप्रदेश

शेडिंग सिर्फ चित्र पर नहीं,इतिहास की समझ पर भी है
डांसिंग गर्ल पर परदा : इतिहास से संवाद या इतिहास पर संदेह?

इतिहास बदलने के लिए बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती,कभी-कभी एक छोटी-सी शेडिंग ही काफी है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल आज इसी कारण विवाद में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग 4500 वर्ष पुरानी (2500-2300 ईसा पूर्व) यह प्रतिमा भारतीय पुरातत्व की महत्वपूर्ण धरोहरों में गिनी जाती है। एक हाथ कमर पर रखे आत्मविश्वास से खड़ी यह किशोरी केवल कलाकृति नहीं,बल्कि उस सभ्यता की सहजता,कलाबोध और आत्मविश्वास का प्रमाण है। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला शिक्षा पुस्तक'मधुरिमा' में उसके नग्न धड़ को शेडिंग से ढक दिया गया। मामूली दिखने वाला यह बदलाव राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। सवाल प्रतिमा का नहीं,उस दृष्टि का है जिससे हम अपने अतीत को देख रहे हैं। क्या हम इतिहास को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर रहे हैं,या उसे अपने समय की नैतिक कसौटियों के अनुरूप बदल रहे हैं?

डांसिंग गर्ल केवल प्रतिमा नहीं,एक सभ्यता का आत्मविश्वास है। लॉस्ट-वैक्स तकनीक से बनी यह 10.5 सेंटीमीटर कांस्य मूर्ति दिखाती है कि सिंधु सभ्यता धातु-कला, सौंदर्य-बोध और रचनात्मकता में कितनी विकसित थी। उसकी मुद्रा उस समाज की सहजता का प्रमाण है,जहाँ शरीर संकोच का विषय नहीं था। दशकों तक यह प्रतिमा एनसीईआरटी की पुस्तकों में बिना बदलाव प्रकाशित होती रही और लाखों विद्यार्थियों ने इसे इतिहास के प्रमाण के रूप में देखा। ऐसे में अचानक इसे उम्र के अनुकूल बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इतिहास को इतिहास की तरह दिखाना अब पर्याप्त नहीं है? यह बदलाव केवल चित्र का नहीं,बल्कि उस सोच का है जो अतीत को उसकी वास्तविकता से नहीं, बल्कि वर्तमान की असहजताओं से परिभाषित करती है।

यह बदलाव केवल संपादन नहीं, इतिहास की पुनर्रचना जैसा है। इतिहासकार मिशेल डैनिनो ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे सेंसरशिप और फर्जी कलाकृति का निर्माण बताया। उनका तर्क था कि किसी ऐतिहासिक वस्तु का मूल रूप बदलने पर विद्यार्थी वास्तविक इतिहास नहीं, बल्कि उसका संपादित संस्करण देखते हैं–यह बौद्धिक अन्याय है। उन्होंने इसे प्राचीन भारत पर विक्टोरियन नैतिकता थोपने की

कोशिश भी कहा। विडंबना यह है कि जिस सभ्यता ने कला को सहज स्वीकार किया, उसके प्रतीकों पर आज कृत्रिम शालीनता लादी जा रही है। जबकि इतिहास का काम सुविधा के अनुसार बदलना नहीं,बल्कि असुविधाजनक सच्चाइयों से रूबरू कराना है।

यह विवाद भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की समझ पर सवाल खड़ा करता है। खजुराहो के मंदिर,कोणार्क का सूर्य मंदिर,अजंता-एलोरा की चित्रकला और गुप्तकालीन मूर्तिशिल्प बताते हैं कि भारतीय कला में मानव शरीर सदैव सौंदर्य और अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। यहाँ नग्नता को अश्लीलता नहीं, बल्कि स्वाभाविकता,शक्ति, सृजन और सौंदर्य का प्रतीक माना गया। कामसूत्र की परंपरा वाली इस सभ्यता में यदि आज अपनी ही कलात्मक विरासत पर असहजता होने लगे,तो प्रश्न उठता है–बदल इतिहास रहा है या हमारी दृष्टि? डांसिंग गर्ल की नग्नता अश्लीलता नहीं, उस युग की सांस्कृतिक सहजता का प्रमाण है। उसे ढकने का प्रयास उस समझ को ढकने जैसा है,जिसने उस कला को जन्म दिया था।

इस विवाद की एक और परत भीतर का विरोधाभास खोलती है। एन सी ई आर टी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में यही प्रतिमा अपने मूल रूप में है,जबकि कक्षा 9 की कला शिक्षा पुस्तक में उसका संशोधित रूप दिखाया गया है। एक ही संस्था की दो पुस्तकों में एक ही ऐतिहासिक वस्तु के दो अलग-अलग रूप शिक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं। क्या हम छात्रों को इतिहास पढ़ा रहे हैं या उसे अपने वर्तमान मानकों के अनुसार ढाल रहे हैं? यह केवल एक चित्र का मामला नहीं,बल्कि उस प्रवृत्ति का संकेत है जहाँ पाठ्यक्रम संशोधन के नाम पर इतिहास और पुरातत्व पर वैचारिक दबाव दिखने लगता है। जब तथ्य बदलते हैं, तो शिक्षा का आधार कमजोर पड़ता है।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता का तर्क नकारा नहीं जा सकता। कुछ अभिभावक और शिक्षक मानते हैं कि किशोर विद्यार्थियों के सामने नग्नता का प्रदर्शन सावधानी से होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है–समाधान समझाना है या छिपाना? शिक्षा का दायित्व संदर्भ देना है,न कि तथ्य बदलना। यदि किसी कलाकृति में नग्नता है, तो छात्रों को बताया जा सकता है कि प्राचीन कला में उसका अर्थ आधुनिक दृष्टि से अलग था–वह शक्ति,सौंदर्य,स्वतंत्रता और स्वा भाविकता का प्रतीक भी हो सकती है। हर असहज तथ्य पर शेडिंग चढ़ाते रहेंगे तो अगली पीढ़ी इतिहास नहीं, उसका सुविधाजनक संस्करण पढ़ेगी। तब पाठ्यपुस्तकें दस्तावेज़ कम और कल्पना अधिक बन जाएँगी।

शिक्षा मंत्रालय के स्पष्टीकरण और सार्वजनिक आलोचना के बाद एन सी ईआर टी ने मूल छवि बहाल करने का निर्णय लिया। डिजिटल संस्करण में तुरंत संशोधन हुआ और भविष्य की मुद्रित प्रतियों में भी मूल प्रतिमा प्रकाशित करने की घोषणा की गई। यह कदम स्वागत योग्य है,लेकिन सवाल छोड़ता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन क्यों किया गया। यह निर्णय दिखाता है कि पाठ्यपुस्तकें अब केवल शैक्षणिक सामग्री नहीं,बल्कि वैचारिक संघर्ष का भी हिस्सा बन चुकी हैं। यह घटना याद दिलाती है कि संवेदनशीलता और सेंसरशिप की रेखा बहुत पतली है,और उसे पार करने पर संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

डांसिंग गर्ल विवाद किसी प्रतिमा का नहीं,हमारे आत्मविश्वास का है। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी यह डांसिंग गर्ल हर वर्ष असंख्य विद्यार्थी और पर्यटक देखते हैं,और कोई उसे अश्लीलता नहीं,बल्कि भारतीय सभ्यता की उपलब्धि मानता है। यदि हम अपनी विरासत को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसके गौरव पर गर्व भी अधूरा है। इतिहास को ढक देने से वह बदलता नहीं,केवल हमारी समझ सीमित होती है। पाठ्यपुस्तकें ज्ञान की खिड़कियाँ हैं,नैतिकता की दीवारें नहीं। डांसिंग गर्ल को उसकी पूर्ण वास्तविकता के साथ स्वीकार करना ही उस सभ्यता का सच्चा सम्मान है,जिसने हजारों वर्ष पहले आत्मविश्वास को कांस्य में ढाल दिया था।

आत्मनिर्भरता स्वाभिमानी राष्ट्र का प्रतीक

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है,इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है,बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है। एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई,पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं,पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 75 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है,वह कर्जे से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलाने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान,टेक्नोलॉजी,मेडिकल साइंस,इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज,स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह संघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताबें लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी।

हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रेषित हुआ आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है।महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दैव दैव आलसी पुकारा है,तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्म विश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है,आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से आगे बढ़ने वाला देश या व्यक्ति या समाज सदैव प्रफुल्लित आत्म विश्वासी तथा विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता है। हमें सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास,छिपी हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त होता है। पराधीन देश सामान्य व्यक्ति सदैव पशु तुल्य होते हैं। जिनका अपना कोई विचार या व्यक्तित्व नहीं हो सकता है।

बदलाव ही जीवन है...

चन्द्रकांत खूंटे
जांजगीर-चांपा,छत्तीसगढ़

मेघों का गर्जन हुआ,वृष्टि की मूक
बूंदें धरा पर गिरीं,
और कर्ण-पटल से छूकर,
धीर से एक शाश्वत सत्य कह गईं...
कि ताप किसी का भी हो
वो चिरस्थाई नहीं रहता!
देखो उस प्रचंड दिवाकर को
जो मध्याह्न में संपूर्ण नभ को
दहकाता है
अहंकार से तप्त,स्वर्ण-
किरणों को बिखेरता है,
पर नियति के नियम अनुसार
संध्या की गोद में उसे भी
नतमस्तक होना पड़ता है,
शीतल चंद्रमा के सम्मुख,अपना
तेज खोना पड़ता है।
कठोर पाषाण को चीरती
वेगवती, मदमस्त वो सरिता
जो पर्वतों के अहंकार को
खंडित करती थी
अंततः विशाल जलधि के
आलिंगन में खोकर
शांत, गंभीर और नीरव हो जाती है।
जीवन का दर्शन-यह काल-चक्र
निरंतर गतिमान है,
वैभव,यौवन और सत्ता का मद
सब क्षणभंगुर हैं,सब नश्वर हैं।
पतझड़ के अवसाद के बाद ही
नव-पल्लव का सृजन
स्वीकार्य होता है।
इसलिए,हे मानव !इस क्षणिक
उत्ताप पर कैसा विस्मय?
जब प्रकृति स्वयं गवाही देती है,
कि यहाँ किसी का भी वर्चस्व
सदा सर्वदा के लिए
अटल नहीं रहता!

12987 परमाणु बमों पर टिकी दुनिया के मध्य भारत की सामरिक स्थिति

दुर्गेश राय
गोरखपुर,
उत्तरप्रदेश

92,100,000,000 डॉलर। यह वह विशाल धन राशि है जिसे भारत ने केवल एक वर्ष में अपनी सेना और हथियारों पर खर्च कर दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जून 2026 की वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक सुरक्षा की एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करती है। परमाणु-संपन्न देशों ने दुनिया को एक बार फिर बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। पूरी दुनिया में इस समय 12,187 परमाणु हथियार मौजूद हैं जिसमे से 9745 सेना के पास,4012 मिसाइल या विमान पर तैनात हैं और 1200 से अधिक तो हाई एलर्ट मोड में हैं। यह संख्या पूरी मानवता को कई बार नष्ट करने के लिए काफी है। शीतयुद्ध के बाद दुनिया अब सबसे खतरनाक और अस्थिर दौर से गुजर रही है।

सिपरी एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी स्थापना 1966 ई0 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी जिसके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट 'सिपरी इयरबुक-2026'के अनुसार दुनिया भर में शांति और निरस्त्रीकरण के कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह विफल हो चुके हैं। विभिन्न देशों के बीच अब आधुनिक हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो चुकी है। प्रमुख देश अब अंतरराष्ट्रीय कानूनों के बजाय केवल सैन्य शक्ति और परमाणु प्रतिरोध पर निर्भर हैं। पुराने द्विपक्षीय समझौते अब प्रभावी नहीं रहे। पारंपरिक युद्धों का स्वरूप बदल चुका है। अब युद्ध के मैदान में साइबर ऑपरेशन्स,घातक ड्रोन और आर्टि फिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ा है। सिपरी ने सचेत किया है कि इन नई तकनीकों के सैन्य उपयोग से वैश्विक टकराव का जोखिम चरम पर पहुंच गया है। वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में सिपरी की रिपोर्ट एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करती है। आर्थिक मंदी के बावजूद

दुनिया भर की सरकारों ने अपने रक्षा बजटों में अप्रत्याशित वृद्धि की है। वैश्विक सैन्य खर्च की इस सूची में अमेरिका 954 बिलियन डॉलर के साथ हमेशा की तरह पहले स्थान पर बना हुआ है जो पूरी दुनिया के सम्पूर्ण सैन्य खर्च का एक तिहाई है। दूसरे स्थान पर 336 बिलियन डॉलर के साथ चीन है जो पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है। तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः रूस और जर्मनी मौजूद हैं। इस सूची में भारत 92.1 अरब डॉलर के रक्षा खर्च के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत के सैन्य बजट में 8.9 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत का यह भारी-भरकम सैन्य खर्च सीमाओं पर जारी गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती के कारण भारत को अपनी सेना को लगातार आधुनिक बनाना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अब घरेलू स्तर पर हथियारों की खरीद के लिए आरक्षित किया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके बावजूद वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक अलग विरोधाभास को सामने लाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण यूक्रेन इस समय वैश्विक हथियारों के आयात में भारत को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।

वैश्विक हथियारों के कुल आयात में 8.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। भारत का अभी भी बड़ा आयातक बने रहना यह साबित करता है कि रक्षा प्रणालियों के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है। भारत वर्तमान में लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नौसैनिक इंजनों का बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है। हालांकि अब भारत के आयात स्रोतों में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव आया है। रूस पर भारत की पारंपरिक निर्भरता पहले की तुलना में काफी कम हुई है। अब फ्रांस, अमेरिका और इजरायल जैसे देशों से हथियारों का आयात बढ़ा है। इसके साथ ही भारत का अपना रक्षा निर्यात भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

परमाणु शस्त्रागार के मोर्चे पर सिपरी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है। कुल वैश्विक परमाणु हथियारों का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा अकेले रूस और अमेरिका के पास केंद्रित है। इसके बाद चीन का स्थान आता है जो अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार सबसे तेज गति से कर रहा है। सिपरी का अनुमान है कि जनवरी 2026 तक भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 180 थी।

इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला दावा भारत की परमाणु नीति में आए एक बड़े बदलाव को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार शांति काल के दौरान अपने कुछ परमाणु हथियारों को तैनात यानी पूरी तरह सक्रिय स्थिति में रखा है। माना जा रहा है कि ये हथियार भारत की परमाणु-सशस्त्र पनडुब्बियों पर गश्त के दौरान तैनात किए गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यदि सिपरी का यह रणनीतिक अनुमान सही है, तो यह चीन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की क्षमता को और अधिक मजबूत करने की नीति को दर्शाता है।

वैश्विक शांति व्यवस्था के संदर्भ में भी सिपरी ने अपनी एक उप-रिपोर्ट में बेहद चिंताजनक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2025 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिकों की कुल संख्या घटकर केवल 79,000 रह गई है,जो पिछले 25 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों के आपसी मतभेदों के कारण नए शांति मिशनों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इस रिपोर्ट ने एक बड़े वैश्विक अंतर्विरोध को भी उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र के इन शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिकों का योगदान देने वाले शीर्ष दस देश भारत सहित ग्लोबल साउथ से हैं। इसके विपरीत इन मिशनों की नीतियां तय करने और वित्तीय नियंत्रण रखने का अधिकार केवल पश्चिमी देशों के पास है। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा प्रशासन में तत्काल सुधार की मांग को रेखांकित करती है।

सिपरी ने आधुनिक युद्ध के बदलते और अदृश्य तरीकों पर भी प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त सैन्य गतिरोध हुआ था। सिपरी के अनुसार इस गतिरोध में दोनों देशों ने पहली बार एक-दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर ऑपरेशन्स का उपयोग किया था। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा की चुनौतियां अब भौगोलिक सीमाओं से निकलकर डिजिटल डोमेन में प्रवेश कर चुकी हैं।

सिपरी ईयरबुक 2026 वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर एक गंभीर चेतावनी है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि दुनिया अब हथियारों के नियंत्रण के दौर से पूरी तरह बाहर आ चुकी है। भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट देश की संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच एक कठिन संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

जुदाई इंसानी भावनाओं का सबसे गहरा अनुभव

संजय गोस्वामी,पटना,बिहार

प्यार को इंसान की जिंदगी का सबसे पुराना और गहरा अनुभव माना जाता है। जन्म के समय इंसान को जो पहली एनर्जी महसूस होती है,वह प्यार है। यह माँ का प्यार,पिता की पत्नी सुरक्षा और परिवार का प्यार है। इसी वजह से प्यार को जिंदगी की नींव कहा जाता है। यह सिर्फ़ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं है,बल्कि इंसान के अंदर का वह इमोशन है जो उसे इंसान,पैशनेट और ज़िंदा रखता है। प्यार मन और आत्मा के सार को छूता है और धीरे-धीरे इंसान के नेचर, सोच और व्यवहार में समा जाता है,उसे एक नया रूप देता है। प्यार का असली सार सिर्फ़ लेने में नहीं,बल्कि देने में है। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है,तो वह नैचुरली उसे खुश रखना चाहता है,उसके दुख बांटना चाहता है और उसके साथ चलना चाहता है। इसमें अधिकार कम और अपनापन ज़्यादा होता है। प्यार किसी पर हुक्म नहीं चलाता,बल्कि आज़ादी देता है। प्यार में,सम्मान और भरोसा दो ऐसे पिलर हैं जिन पर कोई भी रिश्ता खड़ा हो सकता है। अगर ये टूट जाएं, तो प्यार खोखला हो जाता है। इसीलिए प्यार का मतलब है साथ रहना,लेकिन चिपके रहना नहीं,प्यार,लेकिन मतलबीपन नहीं। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत है, उतना ही मुश्किल भी है। हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति और ज़रूरतें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हमें जीवित रहने के लिए बच्चे पैदा करने की आवश्यकता होती है। ज़रा सोचिए,अगर दोनों लिंगों में एक औसत पुरुष की तरह ही लगातार यौन इच्छा का उच्च स्तर होता–रिश्ते के शुरुआती हफ़्तों और महीनों की तरह हर घंटे कई बार सेक्स के बारे में सोचना? हम जीवन की अन्य ज़रूरतों और जिम्मेदारियों को भूल जाते और सारा समय एक साथ बिस्तर पर बिताते। हम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते! खाना कौन लाता या खतरों से कौन सावधान रहता? इसके विपरीत,ज़रा सोचिए,अगर दोनों लिंगों में महिलाओं की तुलना में यौन इच्छा कम होती? तनावपूर्ण समय में,हम शायद बच्चे पैदा करना ही बंद कर देते। दरअसल,विलार्ड हार्ले जूनियर ने अपनी किताब हिज़ नीड्स, हर नीड्स : बिल्डिंग एन अफेयर-प्रूफ मैरिज में सेक्स को पुरुषों की प्राथमिक आवश्यकता और प्रेम को महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकता बताया है। मैंने इस विषय पर चर्चा की और महिलाओं से सीधे पूछा,अगर आपको सेक्स या प्रेम में से किसी एक को छोड़ना पड़े,तो आप क्या चुनेंगी? सभी महिलाओं ने उत्तर दिया,सेक्स। फिर मैंने पुरुषों से भी यही सवाल पूछा,और हालांकि उन्हें इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा,उन्होंने निश्चित रूप से प्रेम को छोड़ने की बात कही। बेशक,मैं समझती थी कि यह अंतर हमारी शारीरिक संरचना में निहित है, लेकिन जब मैंने देखा कि कई महिलाओं ने हाथ उठाकर इसकी पुष्टि की,तो मैं सोचने के लिए रुक गई। इसके अलावा,चूंकि महिलाएं मानव जाति की संबंध स्थापित करने वाली होती हैं,इसलिए प्रेम की उनकी स्वाभाविक इच्छा दूसरों से जुड़ने और ऐसे समुदाय बनाने की उनकी आवश्यकता को पूरा करती है जहां आपसी सहयोग और प्रेम अधिक सहज और समन्वित हो। हमारी अलग-अलग इच्छाओं के अन्य प्राकृतिक कारण भी हैं,लेकिन अभी के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। इन अंतरों से हमें क्या लाभ मिलते हैं? सबसे पहले, आपको लाभ होता है क्योंकि आप यहां हैं! अगर चीजें ऐसी नहीं होतीं,तो आपका अस्तित्व ही न होता! इसके अलावा,पुरुषों,आप अपने जीवन में मौजूद महिला को प्यार भरे शब्दों या तारीफों से, स्नेहपूर्ण स्पर्श से,दयालुता दिखाकर या ऐसा कुछ भी करके जो उसे प्रसन्न करे,और भी अधिक आकर्षित कर सकते हैं। उससे पूछें कि उसके लिए प्यार का क्या अर्थ है। आप असल में परिवार की खुशी के लिए नौकरी कर रहे हैं सेक्स खुशी दे रहा है इस कारण से आप अपनी पत्नी से जुड़े हुए हैं लेकिन रिश्ता विश्वास से जुड़ा है लेकिन उस सेक्स लाइफ को पूरा करने के लिए आप अपने माता पिता को हमेशा नज़रअंदाज़ करते हैं जो गलत है मन पर काबू करें,अच्छे इंसान के लिए माता पिता स्वाभिमान के लिए जुदाई हो सकती है प्यार हमेशा अपने साथ जुदाई का एहसास लेकर चलता है। जुदाई का मतलब सिर्फ़ दूरी नहीं है, बल्कि वो दर्द है जिसमें इंसान बार-बार अपने अंदर उस प्यार की चीख सुनता है जिसे वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं पाता। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हालात हमें उससे अलग कर देते हैं,तो हमारे दिल में जो दर्द उठता है, वो जुदाई ही है। ये दर्द इंसान को न सिर्फ़ बेचैनी से भर देता है बल्कि उसे उस प्यार की गहराई का एहसास भी कराता है। जुदाई वो पल होता है जब इंसान अपने दिल के सबसे कोमल हिस्सों का सामना करता है। जुदाई इंसानी भावनाओं का सबसे गहरा अनुभव है। इस अनुभव में अक्सर यादें अहमियत रखती हैं। किसी अपने की हल्की सी मुस्कान, कोई पुरानी बातचीत,कोई आम सी जगह, सब अचानक मतलब रखने लगते हैं। जुदाई इस बात का सबूत है कि प्यार अभी भी मौजूद है। कभी-कभी,जब हम आमने-सामने होते हैं, तब भी हमें जुदाई महसूस होती है,क्योंकि दूरी सिर्फ़ शरीर की नहीं,मन की भी होती है। और जब मन को दूरी महसूस होती है, तो अंदर एक नई सेंसिटिविटी पैदा होती है। जुदाई इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। उसने क्या पाया,क्या खाया,क्या सीखा,सब प्यार के लिए। वो इन सब के बारे में बार-बार सोचता है। यह अनुभव इंसान को अंदर से तेज़ और बेहतर बनाता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

बिजली दर वृद्धि,स्मार्ट मीटर और अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस का घेराव

भारी बारिश में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता,मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन...

कांग्रेस नेता बोले...बिजली महंगी,व्यवस्था बदहाल और जनता पर बढ़ता जा रहा आर्थिक बोझ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

प्रदेश में बिजली दरों में वृद्धि,ईंधन प्रभार,स्मार्ट मीटर और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने नमना स्थित विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल कृष्णा पाठक के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष,मोर्चा एवं संगठन प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भारी बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर 'बिजली दर वृद्धि वापस लो','अदाणी का स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो','जनता पर आर्थिक बोझ डालना बंद करो' जैसे नारे लगाए और विद्युत विभाग के कार्यालय तक मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण आम जनता लगातार बढ़ते बिजली बिलों और खराब बिजली व्यवस्था से परेशान है।

बिजली दर वृद्धि और ईंधन प्रभार वापस लेने की मांग : कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में हाल ही में बढ़ाई गई विद्युत दरों तथा 12 प्रतिशत की दर से लगाए गए ईंधन प्रभार को तत्काल वापस लेने की मांग की। पार्टी नेताओं का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच बिजली की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं,किसानों,छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक ओर लोगों की आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर बिजली,पानी, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाओं की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिजली दरों में बढ़ोतरी जनविरोधी निर्णय साबित हो रही है।

अंबिकापुर की बिजली व्यवस्था पर भी उठाए सवाल : ज्ञापन में अंबिकापुर शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शहर में लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है,जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण मेंटेनेंस कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। नतीजतन छोटी-छोटी तकनीकी समस्याएं भी लंबे समय तक बनी रहती हैं और उपभोक्ताओं को घंटों बिजली संकट झेलना पड़ता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि शहर की संपूर्ण बिजली व्यवस्था कुछ ठेका कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दी गई है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उपभोक्ताओं से नियमित रूप से बिल और विभिन्न शुल्क वसूले जा रहे हैं, तो उन्हें निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति क्यों नहीं मिल पा रही है?

'बिजली बिल हाफ योजना' दोबारा लागू करने की मांग : कांग्रेस ने सरकार से बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने के साथ-साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लोकप्रिय 'बिजली बिल हाफ योजना' को पुनः लागू करने की मांग भी की। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस योजना से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली थी और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में ऐसी जनहितकारी योजना की आवश्यकता पहले से अधिक है।

'जनता महंगी बिजली और खराब व्यवस्था दोनों झेल रही' : प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों का बिजली बिल कई गुना बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी लगातार बदहाल होती जा रही है। भीषण गर्मी और उमस के मौसम में बार-बार बिजली गुल होने से आम नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी और मरीज सभी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार बिजली दरों में वृद्धि कर रही है तो उसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में जनता महंगी बिजली और खराब व्यवस्था दोनों का सामना कर रही है।

स्मार्ट मीटर को बताया उपभोक्ताओं के साथ धोखा

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। ज्ञापन में कहा गया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अनेक उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत से अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण उपभोक्ताओं को अनुबंधित भार से अधिक खपत दर्शाकर बिल भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में अनुबंधित भार के उल्लंघन का अतिरिक्त सरचार्ज लगाकर उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को आम जनता के साथ धोखा बताते हुए इसकी तकनीकी जांच कराने और इसे अनिवार्य करने के बजाय स्वैच्छिक बनाए जाने की मांग की है।

चेतावनीः मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा तेज

प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बिजली दरों में की गई वृद्धि वापस नहीं ली गई, स्मार्ट मीटर व्यवस्था की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई और अघोषित बिजली कटौती पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि बिजली केवल एक सेवा नहीं बल्कि हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए सरकार को राजस्व बढ़ाने के बजाय उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। सरगुजा में हुआ यह घेराव प्रदेशभर में बिजली दरों, स्मार्ट मीटर और बिजली आपूर्ति को लेकर बढ़ती जन असंतोष की भावना का संकेत माना जा रहा है।

बिजली दर वृद्धि पर टीएस का हमला,बोले...

जनता पर बोझ डाल रही भाजपा सरकार

स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली बिल हाफ योजना बहाल करने की मांग, रामगढ़ व रेत खनन पर भी सरकार को घेरा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पांचवीं बार बिजली की दरें बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। उन्होंने बढ़ी हुई दरें वापस लेने, स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली बिल हाफ योजना दोबारा लागू करने की मांग की। सिंहदेव ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी की गई है। कृषि पंपों की बिजली दरों में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार पांचवीं बार बिजली दरें बढ़ाई गई हैं,जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में बिजली की दरें नहीं बढ़ाईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी,जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया।

साथ ही 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार भी उपभोक्ताओं पर डाला गया है। उनका दावा था कि जून माह में लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल औसतन तीन गुना तक बढ़कर आए हैं।

स्मार्ट मीटर पर उठाए सवाल

टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत से अधिक बिजली दर्ज कर रहे हैं। बिना उपभोक्ता की सहमति के अनुबंध भार बढ़ाकर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है, छत्तीसगढ़ में भी जनहित में इस व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए।

रामगढ़ और रेत खनन का भी उठाया मुद्दा

पत्रकारों के सवालों के जवाब में सिंहदेव ने कहा कि रामगढ़ के अस्तित्व और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कोरिया जिले में रेत खनन से जुड़े हत्या के मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि रेत माफिया सक्रिय हैं। सरकार को रेत खनन की वर्तमान ठेका व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए।

स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता परेशान

जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के कारण आम उपभोक्ता आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत,पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की,हेमंत सिन्हा, इंद्रजीत सिंह धंजल, हेमंत तिवारी, मदन जायसवाल, दुर्गेश गुप्ता, सीमा सोनी, अनूप मेहता, मोहम्मद इस्लाम सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

स्व.कलावती देवी की स्मृति में ऑल इंडिया मैराथन 20 जून को

पुरुष वर्ग के लिए 51 व महिला वर्ग के लिए 31 हजार प्रथम पुरस्कार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में स्व. कलावती देवी की स्मृति में ऑल इंडिया मैराथन का आयोजन 20 जून को सुबह साढ़े पांच बजे से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता खेल प्रेमियों और धावकों के लिए एक बड़ा अवसर है। प्रतियोगिता में 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के युवक, युवती, किशोर हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन का शुभारंभ और समापन स्थल गांधी स्टेडिम से होगा। निःशुल्क पंजीयन के चलते प्रतिभागियों ने उत्साह दिखाया और बड़ी संख्या में महिला, पुरूष प्रतिभागियों द्वारा पंजीयन कराया गया है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला प्रतिभागियों के लिए अलग- अलग पुरस्कार राशि रखी गई है। पुरुषों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 51 हजार रूपए, द्वितीय 21 हजार रूपए और तृतीय 11 हजार रूपए रखा गया है। महिलाओं की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 31 हजार रूपए, द्वितीय 21 हजार रूपए, तृतीय 15 हजार रूपए और चतुर्थ पुरस्कार पांच हजार रूपए निर्धारित है। प्रतियोगिता में चौथे से दसवें और ग्यारहवें से बीसवां स्थान हासिल करने वाले धावकों के लिए भी इनाम रखी गई है, जिसमें पुरूष व महिला वर्ग दोनों के लिए चौथे से दसवां स्थान पर 2100-2100 रूपए, ग्यारहवें से बीसवें स्थान के लिए 1100-1100 रूपए का पुरस्कार व शील्ड दिया जाएगा। पंजीयन 18 जून तक होगा।

बाइक से गिरकर घायल किशोर की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

बाइक से अनियंत्रित होकर गिरे किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतक अमित कुजूर पिता सुरेश कुजूर 17 वर्ष, दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा, सरनापारा का रहने वाला था। बुधवार को वह जमदरहा स्थित स्कूल में कक्षा 10वीं का टीसी लेने के लिये मोटरसायकल में गांव के ही साथी रोहित और आशीष के साथ गया था। गांव वापस आने के बाद वह अपने साथियों को घर छोड़ा और शाम को घर जा रहा था। इसी दौरान पाटीपारा में अनियंत्रित होकर मोटरसायकल सहित खेत में गिर गया। इसकी जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे तो अमित खेत में ही अचेत अवस्था में पड़ा था। घायल को मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर स्वजन पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

कीटनाशक का सेवन की महिला की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

शराब के नशे में अज्ञात कारणों से महिला कीटनाशक का सेवन कर ली, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया, एमसीबी जिला के नागपुर, पोड़ी की फुलेश्वरी पति मोहन सिंह 26 वर्ष, 16 जून को शराब पी थी और नशे की हालत में कीटनाशक का सेवन कर ली। शाम को करीब 6 बजे उल्टी करने और कीटनाशक का गंध आने पर स्वजन को इसका पता चला, और वे उसे नागपुर स्वास्थ्य केन्द्र ले गये। यहां से रिफर करने पर बैकुंठपुर फिर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां 17 जून को इलाज के दौरान दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

निजी जमीन पर अवैध खुदाई का आरोप ग्रामीणों ने एसईसीएल के खिलाफ खोला मोर्चा

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन और आत्मदाह की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

उदयपुर तहसील के ग्राम परसोड़ी कला के ग्रामीणों ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) पर निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर जबरन खुदाई कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खुदाई कार्य पर तत्काल रोक लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिसंबर 2025 को एसईसीएल के अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना, ग्रामसभा की अनुमति और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए जेसीबी मशीन से उनकी निजी जमीन पर खुदाई शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिवार कई पीढ़ियों से उक्त भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया, न मुआवजा मिला और न ही पुनर्वास की जानकारी दी गई। कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों की मौजूदगी की सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की मांग की। इस दौरान

कुछ देर के लिए विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद तहसीलदार लौट गए। बाद में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नंगे पांव सत्याग्रह के संयोजक राजेश सिंह सिसोदिया ने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित परिवार अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन के साथ आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

ग्रामसभा ने भी उठाई कार्रवाई की मांग : ग्राम पंचायत परसोड़ी कला के सरपंच, उपसरपंच,ग्रामसभा अध्यक्ष और प्रभावित ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन में मांग की है कि अवैध कब्जा और खुदाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि भूमि अधिग्रहण का कोई वैध आदेश है तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पर निजी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेंगे।

मारपीट और धमकी मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार,न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र में गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया,जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इससे पहले इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, मायापुर निवासी आकाश जायसवाल ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 मई 2026 को राहुल सिंह और विवेक उपाध्याय उर्फ गोलू पंडित ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की थी। इस घटना की शिकायत दर्ज कराने के बाद जब वह 17 मई को घर लौट रहा था, तब चांदनी चौक स्थित शास्त्री ऑटो के पास दोनों आरोपियों ने उसे फिर घेर लिया। प्रार्थी का आरोप है कि दोनों ने रिपोर्ट दर्ज कराने से नाराज होकर अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी तथा बेल्ट, लोहे की रॉड और मुक्कों से हमला किया। इस दौरान राहुल सिंह ने उसके हाथ में दांत से काटकर भी चोट पहुंचाई। मारपीट में युवक के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई थीं। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 320/2026 दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत विवेचना शुरू की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी राहुल सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका था,जबकि दूसरा आरोपी विवेक उपाध्याय उर्फ गोलू पंडित फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने लगातार तलाश के बाद फरार आरोपी विवेक उपाध्याय उर्फ गोलू पंडित (29 वर्ष),निवासी चांदनी चौक,मायापुर,अंबिकापुर को गिरफ्तार कर लिया।

विद्यालयों में योग दिवस को जनभागीदारी के साथ मनाने के दिए निर्देश...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल एवं प्रभावी आयोजन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा की अध्यक्षता में जिला शिक्षा कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी,बीआरसीसी, प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक उपस्थित रहे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. झा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर शासन एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी अधिकारियों एवं संस्थाओं को आवश्यक तैयारियां समयपूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है तथा इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इसलिए योग दिवस का आयोजन उत्साह एवं व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। डॉ. झा ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं संकुल समन्वयकों को निर्देशित किया कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों, पालकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

चोरी के शक में दंपती की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान पति की मौत

एमसीबी जिले के कठौतिया गांव की घटना,महिला भी घायल,हत्या का मामला दर्ज करने की तैयारी,आरोपियों की तलाश जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर/एमसीबी,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

चोरी के शक में ग्रामीणों द्वारा की गई बेरहमी से मारपीट में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई,जबकि उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। घटना एमसीबी जिले के कठौतिया गांव की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद अब हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक राजकुमार (निवासी ग्राम पमखेड़ी,जिला सागर, मध्यप्रदेश) अपनी पत्नी परमिला के साथ ससुराल कठौतिया आया था। परमिला करीब डेढ़ माह पहले अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए मायके आई थी।

बताया गया कि 14 जून की रात करीब एक बजे शराब के नशे में राजकुमार ने पत्नी से अपने साथ सागर चलने को कहा। पत्नी के बीमार पिता को छोड़कर जाने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद राजकुमार घर से निकल गया। पति की तलाश में निकली परमिला देर रात करीब तीन बजे बिछली गांव पहुंची, जहां वह सड़क किनारे मिला। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और दोनों पर

चोरी करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि ग्रामीणों ने डंडे, लात-घूंसों से दंपती की पिटाई कर दी। हमले में राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि परमिला के चेहरे, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। घटना के बाद किसी तरह महिला अपने मायके पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। दोनों को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर राजकुमार को मनेन्द्रगढ़ से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान महिला की नाक में पहनी सोने की नथ, पायल और नकद राशि भी गायब हो गई। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

शराब कोचियों पर उठे सवालों के बीच बड़ी कार्रवाई...

आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता हुये निलंबित

जिला आबकारी अधिकारी और मंडल प्रभारी को मिला नोटिस...

क्या शराब कोवियों के संरक्षणदाता थे जिम्मेदार अधिकारी? कार्रवाई ने तेज की बहस...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा में अवैध शराब कारोबार,शराब कोचियों की सक्रियता और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बौरीपारा में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी उपनिरीक्षक एवं वृत्त प्रभारी अंबिकापुर अनिल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है,जबकि जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ और मंडल प्रभारी शीला बाड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब शहर में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि सरकारी शराब दुकानों के अलावा भी कई इलाकों में कथित कोचियों के माध्यम से आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है। जनमानस में लगातार यह सवाल उठ रहा था कि यदि विभाग नियमित अभियान चला रहा है तो फिर अवैध बिक्री और ओवररेटिंग जैसी शिकायतें बार-बार क्यों सामने आ रही हैं।

आयुक्त ने कहा...क्षेत्र में गंभीर अनियमितता नियंत्रणहीनता का प्रमाण : आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह दुकान अनिल गुप्ता के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उनके क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण का परिचायक है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय सरगुजा निर्धारित किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी और मंडल प्रभारी से भी मांगा जवाब : केवल उपनिरीक्षक पर कार्रवाई तक मामला सीमित नहीं रहा। आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ और मंडल प्रभारी शीला बाड़ा को भी कारण बताओ सूचना जारी की है। नोटिस में कहा गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार की अनियमितता सामने आना नियंत्रण की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। दोनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

उड़नदस्ता टीम ने किया था छद्म खरीदार के जरिए परीक्षण

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने 16 जून को विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बौरीपारा का आकस्मिक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान छद्म ग्राहक बनाकर शराब खरीदी गई। जांच में पाया गया कि विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव ने गोल्डन गोवा व्हिस्की के 20 पाव की बिक्री शासन द्वारा निर्धारित 2400 रुपये के बजाय 2500 रुपये में की। यानी ग्राहक से 100 रुपये अतिरिक्त वसूले गए। उड़नदस्ता ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया।

अब उठ रहे बड़े सवाल...

यह कार्रवाई सामने आने के बाद शहर में पहले से चल रही चर्चाओं को नया बल मिला है। लंबे समय से लोग पूछते रहे हैं कि:

- यदि आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा था तो शराब कोचियों का नेटवर्क समाप्त क्यों नहीं हुआ?
- क्या कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं और अंतिम स्तर के लोगों तक सीमित रही?
- क्या विभाग को पहले से शिकायतें मिलती रही थीं?
- यदि मिलती थीं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई?
- क्या ओवररेटिंग और अवैध बिक्री के मामलों में उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई थी?
- जिन क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आती रहीं, वहां निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी?

संरक्षण के आरोप सिद्ध नहीं, लेकिन कार्रवाई ने बढ़ाई शंकाएं

शहर में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि किसी भी अधिकारी के खिलाफ संरक्षण देने का आरोप अभी तक किसी न्यायिक या विभागीय जांच में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे आरोपों को तथ्यात्मक रूप से स्थापित दावा नहीं माना जा सकता। लेकिन अब जबकि स्वयं आबकारी आयुक्त ने अनिल गुप्ता को गंभीर लापरवाही और शिथिल नियंत्रण के आधार पर निलंबित किया है तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है, तब यह प्रश्न और प्रासंगिक हो गया है कि आखिर विभागीय निगरानी व्यवस्था में चूक कहां हुई।

शराब कोचियों पर उठे सवालों के बीच बड़ी कार्रवाई: आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता निलंबित, जिला आबकारी अधिकारी और मंडल प्रभारी को नोटिस

जनता चाहती है पूरी सच्चाई सामने आए

सरगुजा में शराब कोचियों,ओवररेटिंग और अवैध शराब बिक्री की शिकायतें केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं हैं, बल्कि यह सरकारी राजस्व,उपभोक्ता अधिकार और जनस्वास्थ्य से भी जुड़ा विषय है। लोगों की मांग है कि आबकारी विभाग क्षेत्रवार शिकायतों,जांच रिपोर्टों और कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए और उनकी वास्तविक सफलता क्या रही। फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि जिस विभाग पर अवैध शराब और ओवररेटिंग रोकने की जिम्मेदारी थी,उसी विभाग के अधिकारियों पर अब जवाबदेही का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह कार्रवाई केवल एक दुकान तक सीमित रहती है या फिर शराब कारोबार से जुड़े पूरे तंत्र की गहन जांच का रास्ता खोलती है।

सरगुजा के विकास को मिलेगी नई रफ्तार...कैबिनेट मिनिस्टर राजेश अग्रवाल की पहल पर केंद्र ने बढ़ाया कदम

अम्बिकापुर,सीतापुर और पत्थलगांव बायपास को 4-लेन बनाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया संज्ञान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा अंचल की सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को भेजे गए पत्र पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने अम्बिकापुर-पत्थलगांव सेक्शन (एनएच-43) अंतर्गत अम्बिकापुर,सीतापुर एवं पत्थलगांव बायपास को वर्तमान प्रस्तावित टू-लेन के स्थान पर 4-लेन परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी मांग को संबंधित अधिकारियों के पास आवश्यक परीक्षण एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है। यह पहल सरगुजा एवं जशपुर क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अम्बिकापुर से पत्थलगांव तक का यह मार्ग उत्तर छत्तीसगढ़ के प्रमुख संपर्क मार्गों में से एक है, जहां

लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण चैड़ीकरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अम्बिकापुर,सीतापुर एवं पत्थलगांव बायपास को टू-लेन के बजाय 4-लेन परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि यह मार्ग न केवल यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,बल्कि सरगुजा और जशपुर क्षेत्र के पर्यटन, व्यापार, उद्योग,कृषि एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा इस मांग पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाने से भविष्य में परियोजना को गति मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। इस संबंध में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अम्बिकापुर,सीतापुर और पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों की यह लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांग रही है। इस मार्ग का 4-लेन विस्तार होने से न केवल यातायात सुगम और सुरक्षित होगा,बल्कि पर्यटन, व्यापार,कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। मैंने क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से इस विषय पर आग्रह किया था।

उनके द्वारा सकारात्मक संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाना अत्यंत स्वागतयोग्य है। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरगुजा और जशपुर अंचल प्राकृतिक,सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र हैं। बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी,निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से यह महत्वपूर्ण परियोजना शीघ्र आगे बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अम्बिकापुर में होंगे शामिल

अधिकारियों को सौंपे गए विभिन्न दायित्व

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला सरगुजा में मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन का 21 जून 2026 के कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री अम्बिकापुर के राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर में शामिल होगे। उक्त कार्य के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा विनय कुमार अग्रवाल को जिला नोडल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर बनसिंह नेताम को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभाग के अधिकारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे गए हैं। पार्किंग, वाहन, व्यवस्था, ट्रैफिक रूट चार्ट,कानून,ब्लड ग्रुप व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा,हैलीपेड एवं संपूर्ण कार्यक्रम एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु बांस-बल्ली व्यवस्था कराना वन मण्डलाधिकारी अम्बिकापुर, कार्यक्रम के दो दिवस पूर्व हेलीपेड के अक्षांश देशांश की जानकारी एवं दण्डाधिकारी की ड्यूटी लगाना अपर कलेक्टर सुनील नायक एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग जिला सरगुजा वीरेन्द्र चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था एवं कार्यक्रम समाप्ति उपरांत दूसरे दिन पूरे कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई कार्य, कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई के लिए अलग-अलग स्थानों पर डस्टबिन उपलब्ध कराना एवं चलित शौचालय की व्यवस्था हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम अम्बिकापुर डी.एन.कश्यप, प्राटोकाल, कानून व्यवस्था आमंत्रण पत्र का वितरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर वन सिंह नेताम, कार्यक्रम स्थल पर लोगों हेतु बैठक व्यवस्था हेतु अपर कलेक्टर राम सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर शारदा अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती उमा राज, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जे.आर. प्रधान,सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती उषा नेताम एवं नायब तहसीलदार जयेंस कंवर,कार्यक्रम स्थल में डोम एवं ग्रीन रूम के साथ अन्य संपूर्ण व्यवस्था हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निमार्ण वीरेन्द्र चौधरी, कार्यक्रम स्थल में फूलमालाबुके इत्यादि का व्यवस्था करना उप सचलक उद्यान अम्बिकापुर हितेन्द्र सिंह

मेश्राम, मंच पर माननीय अतिथियों के बैठने की व्यवस्था निर्धारित करना, नाम पट्टिका की व्यवस्था, मंच पर बैठने वाले अतिथियों तथा स्वागत करने वालों के नाम सूची उद्घोषकों को उपलब्ध कराने का दायित्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर का होगा,अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर बन सिंह नेताम, तहसीलदार अम्बिकापुर विकास जिन्दल एवं नायब तहसीलदार जयेंस कंवर,कार्यक्रम स्थल पर साउंड सिस्टम मंच एवं आस-पास लाईट,पीए सिस्टम की व्यवस्था,एलईडी स्क्रीन लगवाना सहित आदि कार्यक्रम पर एक दिवस पूर्व साउंड सिस्टम एवं एलईडी स्क्रीन की जांच पड़ताल कर ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करना कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण यांत्रिकी आर.आर. दर्रो एवं सहायक नोडल अधिकारी इ.डी.एम ई-सेवा केन्द्र वैभव सिंह, सतत विद्युत आपूर्ति एवं आपातकालीन जनरेटर की व्यवस्था हेतु कार्यपालन अभियंता छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी (शहरी) जे.पी. राजवाड़े, कार्यपालन अभियंता छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी (ग्रामीण) रोशन नागवंशी, कार्यक्रम स्थल पर जीवन रक्षक दवाईयों के साथ चिकित्सा दल मय एंबुलेंस नियुक्त करना एवं उपचार की व्यवस्था करना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को, सर्किट हाउस में अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु एसडीम बनसिंह नेताम एवं सहायक नोडल अधिकारी कार्यपालन अभियंता लोक निमार्ण विभाग वीरेंन्द्र चौधरी, मुख्यमंत्री जी की अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह तैयार करना सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर ललित शुक्ला एवं जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन गिरीश गुप्ता, पायलेट एवं क्रू मेम्बर हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था हेतु जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ को सौंपी गई है।

बैल की हत्या कर मांस खाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार,पुलिस ने भेजा जेल

-संवाददाता-
बलरामपुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले की गणेश मोड़ चौकी पुलिस ने बैल की हत्या कर उसका मांस खाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325, 3(5) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 और 10 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 जून 2026 को ग्राम सवनी निवासी विकास यादव (32 वर्ष),पिता धनेश्वर यादव ने गणेश मोड़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 15 जून की रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच गांव के कुछ लोगों ने अगस्टीन कोड़ाकू से एक बैल खरीदकर उसे केवाड़ी जंगल ले

गए,जहां उसकी हत्या कर मांस आपस में बांटकर खा लिया। शिकायत मिलने के बाद गणेश मोड़ चौकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 97/2026 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सात आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अकलेस चरगट (26 वर्ष), पौलूस चरगट (30 वर्ष),पीटर हड्डे (25 वर्ष),जेबियर कुम्हरिया (20 वर्ष),नीलम मुरूम (27 वर्ष),रतू कुम्हरिया (45 वर्ष) तथा अल्बिश सदोम (48 वर्ष) शामिल हैं। सभी आरोपी ग्राम सवनी,चौकी गणेश मोड़,जिला बलरामपुर के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 17 जून 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पशु क्रूरता और कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026
(घटती-घटना)।

शराब पीकर घर पहुंचे युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरगवां बंगालीपारा निवासी गोपाल विश्वास पिता गोकुल विश्वास 32 वर्ष, 17 जून की रात को करीब 9 बजे बस्ती से शराब पीकर आया, और पत्नि, बच्चों के साथ खाना खाने के बाद सोने के लिये चले गया था। देर रात करीब 1.30 बजे पत्नि ममता विश्वास की नींद खुली, तो कमरे में उसका पति नहीं था। कुछ देर इंतजार के बाद भी जब पति नहीं आया तो पत्नि उसे खोजते रसोईघर में पहुंची, यहां उसका पति फांसी पर झूल रहा था। शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और फांसी का फंदा काटकर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां देर रात 2.25 बजे जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 - ..../20 (1)/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका श्रीमती प्रेमलता गोयल आ0/ पति प्रहलाद कृष्ण गोयल जाति निवासी बाबुपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - बाबूपारा, शीट नम्बर-9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3528/35 रकबा 0.04$^{1/2}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-19.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा । आज दिनांक :- 05.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छग)

रा0प्र0क्र0 - 202303021700103/अ-55/2021-22

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नवीन कुमार गुप्ता आ0 स्व0 श्याम सुन्दर गुप्ता, निवासी ग्राम असोला, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा उग के द्वारा ग्राम असोला, प0ह0न0 08 के पटेल पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच कार्यवाही व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक :- 24/07/20268 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 08/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार, अम्बिकापुर-2

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै राजू दास
(माता/पिता/पालक का नाम)
सुपुत्र/सुपुत्री शिवनाथ दास
गाँव/शहर आमाटोली ,तहसील सीतापुर जिला -सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग
सुपुत्र/सुपुत्री का नाम अंशुमाला (पुराना नाम) से बदल कर अंशु दास (नया नाम) रख लिया है।

पालक
राजू दास
आमाटोली,तहसील सीतापुर
जिला -सरगुजा छत्तीसगढ़

शिक्षित बेटियां ही विकसित राष्ट्र की नींव : राजेश अग्रवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शिक्षित बेटियां आत्मनिर्भर समाज और विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला हैं। वे गुरुवार को उदयपुर विकासखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झिरमिटी में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवप्रवेशी छात्राओं का तिलक लगाकर एवं अध्ययन सामग्री भेंट कर स्वागत किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा बेटियों को सशक्त बनाती है और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देती है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा0) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़ (छ.ग.)

नीलाम विज्ञापन

सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि मनेन्द्रगढ वनमण्डल के अधीनस्थ काष्ठागार जनकपुर में उपलब्ध नये, पुराना ईमारती काष्ठ एवं पुराना जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है, इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्सन में अवश्य भाग लेवे। ई-ऑक्सन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार जनकपुर से प्राप्त कर सकते है।

डिपो का नाम - काष्ठागार जनकपुर
नीलाम दिनांक - 25-06-2026
नीलाम समय - प्रातः 09:00 बजे से प्रारम्भ

क्र	प्रजाति	नये अविक्रित काष्ठ		पुराने अविक्रित काष्ठ			
		लट्ठा	बल्ली	लट्ठा		बल्ली	
		घ.मी.	नग	नग	घ0मी0	नग	घ.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0.000	0	229	14.787	3762	43.264
2	साल	190.000	280	12198	1445.639	1607	48.710
3	साजा	0.000	0	3	0.280	2	0.056
4	धावड़ा	0.150	0	9	0.864	1	0.017
5	हल्दू,मुण्डी,बांसा	0.000	0	2	0.087	0	0.000
6	नीलगिरी	0.000	0	0	0.000	717	3.778
	योगः—	195.150	280	12441	1461.657	6089	95.825
7	मिश्रित जलाऊ	100 चट्टा नया		443 चट्टा पुराना			
	योग :—	100 चट्टा नया		443 चट्टा पुराना			

टीपः-
1. क्रेताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व एम. एस. टी. सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वालेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई. एम. डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो एम. एस. टी. सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉग इन करके देख सकते हैं।

जी.नं.-262701477/3

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़

CMYK

राजनीतिक चुप्पी और उठते सवाल...

घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, लोगों का कहना है कि इतने बड़े और संवेदनशील मामले में जनता एक स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रही थी, दूसरी ओर बैकुंठपुर विधायक पीड़ित परिवार से मिले, संवेदना व्यक्त की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की, स्थानीय चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई।

तीन चिताएं और कानून पर भरोसा...

इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार को लेकर कोई शर्त नहीं रखी, न तो सड़क जाम किया गया और न ही प्रशासन के सामने कोई अल्टीमेटम रखा गया, परिवार ने केवल न्याय की मांग की, यह दर्शाता है कि तमाम दुख और आक्रोश के बावजूद परिवार अभी भी कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर रहा है।

बुलडोजर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग...

घटना के बाद जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बुलडोजर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है, लोगों का तर्क है कि यदि यह पूर्व नियोजित और संगठित अपराध है तो इसकी जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए, हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगा।

अब पूरा जिला एक जवाब चाहता है...

आज कोरिया जिले का हर नागरिक एक ही प्रश्न पूछ रहा है क्या यह केवल रेत का विवाद था? क्या यह रसूख और प्रभाव का टकराव था? क्या समझौते के लिए पहुंचे लोगों को सुनियोजित तरीके से मौत के मुंह में धकेला गया? क्या इस मामले में केवल प्रत्यक्ष आरोपी ही जिम्मेदार हैं या पर्दे के पीछे की कड़ियां भी सामने आएंगी? इन सभी सवालों का उत्तर केवल निष्पक्ष जांच, वैज्ञानिक साक्ष्य और न्यायालय की प्रक्रिया ही दे सकती है, लेकिन इतना तय है कि नौगई हत्याकांड ने कोरिया जिले के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिख दिया है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। अब निगाहें पुलिस जांच, न्यायिक प्रक्रिया और उस सत्य पर टिकी हैं जो तीन चिताओं की राख के नीचे कहीं दबा हुआ है।

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत, 18 जून 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी विवाद में गाली-गलौज होती है, धमकियां दी जाती हैं,मारपीट भी हो जाती है, लेकिन जब कोई विवाद इस हद तक पहुंच जाए कि लोगों को वाहन में फंसाकर जिंदा जला दिया जाए,तब वह केवल आपराधिक घटना नहीं रह जाती,बल्कि समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला प्रश्न बन जाती है।

कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगई में घटित सामूहिक हत्याकांड ने पूरे छत्तीसगढ़ को स्तब्ध कर दिया है, जिस तरह से तीन लोगों की मौत हुई,जिस तरह से एक परिवार के लोगों को कथित रूप से घेरकर हमला किया गया, वाहन को टक्कर मारकर फंसाया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया,उसने लोगों के भीतर भय, आक्रोश और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, बैकुंठपुर में दो दिनों के भीतर एक ही परिवार की तीन-तीन चिताएं जलीं,श्मशान घाट में उठता धुआं केवल तीन शवों का नहीं था, बल्कि वह उस भरोसे के जलने का प्रतीक भी था जो आम नागरिक कानून और व्यवस्था पर करता है।

चिरमी रेत खदान से शुरू हुई कहानी

जानकारी के अनुसार पूरे विवाद की जड़ चिरमी रेत खदान को माना जा रहा है,बताया जाता है कि कोरिया जिले की चिरमी रेत खदान का ठेका अंबिकापुर के एक व्यक्ति को मिला था,बाद में संचालन की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदार मयंक सिंह को सौंप दी गई,मयंक सिंह खदान की देखरेख और रेत विक्रय का काम संभाल रहे थे,स्वाभाविक रूप से उनका मानना था कि जब खदान का संचालन वैधानिक रूप से उनके पास है तो क्षेत्र में रेत का व्यापार भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, यहीं से विवाद शुरू हुआ,स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जाते रहे कि कुछ लोग नदी-नालों और अन्य स्थानों से रेत निकालकर बेच रहे थे। इसको लेकर लगातार तनातनी बढ़ती गई। जो विवाद शुरू में व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा था,वह धीरे-धीरे प्रतिष्ठा, प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया।

विधायक, थाना प्रभारी और आरोपियों के सीडीआर जांच की उठ रही मांग...

नौगई सामूहिक हत्याकांड के बाद अब एक नई मांग जोर पकड़ने लगी है, स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक वर्गों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केवल आरोपियों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं होगी,बल्कि घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की भी जांच होनी चाहिए। विशेष रूप से क्षेत्रीय विधायक, तत्कालीन थाना प्रभारी और मामले में नामजद या संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग उठ रही है,सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि रेत विवाद, हूटर हटाने की कार्रवाई और बाद में दर्ज हुए आपराधिक प्रकरण के दौरान विधायक और थाना प्रभारी के बीच कई बार बातचीत हुई थी, यह भी कहा जा रहा है कि घटना वाले दिन थाना प्रभारी किसी अन्य मामले में थाना क्षेत्र से बाहर थे और थाने का प्रभार दूसरे अधिकारी के पास था, ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब दोनों पक्षों के बीच तनाव पहले से मौजूद था और मामला पुलिस तक पहुंच चुका था, तब पर्याप्त सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि यदि विधायक,थाना प्रभारी और मामले से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के सीडीआर की जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि घटना से पहले और बाद में किन-किन लोगों के बीच संपर्क हुआ और किस स्तर पर बातचीत चल रही थी। लोगों का मानना है कि तकनीकी साक्ष्य कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दे सकते हैं और जांच को नई दिशा मिल सकती है,हालांकि अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की भूमिका को लेकर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन जनता का मानना है कि यदि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाती है और सभी संबंधित लोगों के कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल होती है,तो इस बहुचर्चित हत्याकांड से जुड़े कई अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब सामने आ सकता है।

घटती घटना
दिन में एफआईआर, रात में मौत का तांडव!
शाम 4:47 बजे दर्ज हुई मारपीट की रिपोर्ट, कुछ घंटे बाद जलती गाड़ी में मिली लाशें
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले-गुनहगारों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा...
रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए?

नौगई से उठी आग की लपटें
क्या छत्तीसगढ़ की रेत नीति ने पैदा कर दिया अपना 'भिंड-मुरैना'?

रसूखदार परिवार और बढ़ती रंजिश

स्थानीय चर्चाओं में त्रिपाठी परिवार को क्षेत्र का प्रभावशाली परिवार बताया जाता रहा है,लोगों के बीच यह धारणा भी रही कि परिवार की राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मजबूत है,आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि यही प्रभाव समय के साथ विवादों को और जटिल बनाता गया,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है, लेकिन यह निर्विवाद है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था,इसी दौरान एक और घटनाक्रम ने चर्चा बटोरी, क्रेशर संचालक भारत सिंह उर्फ लाला सिंह अपनी गाड़ी में हूटर लगाकर चलते थे,कुछ समय पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हूटर हटवा दिया था,स्थानीय चर्चाओं में यह बात कही जाती रही कि इस कार्रवाई का श्रेय विरोधी पक्ष स्वयं लेता था और इसे अपनी राजनीतिक पहुंच का परिणाम बताता था,हालांकि हूटर हटाना कानूनन उचित कार्रवाई थी,लेकिन दोनों पक्षों के बीच यह घटना भी कटुता का एक नया कारण बन गई।

16 जून: जब विवाद थाने पहुंचा...

16 जून 2026 को मामला सोनहत थाने पहुंच गया,निशांत त्रिपाठी,पिता सत्य प्रकाश त्रिपाठी,ने शिकायत दर्ज कराई कि मयंक सिंह और उनके साथियों ने रास्ता रोककर गाली-गलौज की,धमकी दी और हथियार दिखाया, शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया,यहीं से घटनाक्रम तेजी से बदलता है,एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका थी,ऐसे में कुछ लोगों ने समझौते और बातचीत का रास्ता निकालने का प्रयास किया।

समझौते की पहल और वरिष्ठ लोगों की भूमिका

मयंक सिंह ने अपने क्षेत्र के कुछ सम्मानित और वरिष्ठ लोगों से संपर्क किया, इनमें सबसे प्रमुख नाम था भारत सिंह उर्फ लाला सिंह का,लाला सिंह केवल व्यवसायी नहीं थे। वे पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके थे और बैकुंठपुर तथा सोनहत क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों में उनकी गिनती होती थी,बताया जाता है कि मयंक सिंह उनके पास पहुंचे और उनसे मध्यस्थता का अनुरोध किया,इसके बाद बैकुंठपुर से तीन वाहनों में लोग सोनहत के नौगई की ओर रवाना हुए,एक वाहन में भारत सिंह उर्फ लाला सिंह,उनके चचेरे भाई नागेंद्र सिंह,रिश्तेदार वीरेंद्र सिंह और शिक्षक योगेंद्र सिंह बैठे थे,दूसरे वाहन में मयंक सिंह और उनके कुछ साथी थे,तीसरी बोलेरो में भी कुछ लोग मौजूद थे, जिनकी पूरी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है,सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन लोगों में से अधिकांश मूल विवाद के पक्षकार नहीं थे। वे केवल समझौता कराने और विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से गए थे।

क्या बातचीत के नाम पर बिछाया गया जाल?

यहीं से मामला भयावह रूप लेता है,स्थानीय लोगों,प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के आरोपों के अनुसार जिस स्थान पर बातचीत होनी थी,वहां पहले से चार-पांच टीपर वाहन खड़े थे,आरोप है कि जैसे ही बातचीत के बाद लोग वापस लौटने लगे,अचानक उन पर हमला शुरू हो गया,लाठी,डंडे और अन्य हथियारों से हमला किया गया,बचाव के लिए लोग अपने वाहनों की ओर भागे,इसी दौरान कथित रूप से पहले से तैयार खड़े टीपरों को चालू कर वाहनों में जोरदार टक्कर मारी गई,टक्कर इतनी भीषण बताई जा रही है कि वाहन क्षतिग्रस्त होकर जाम हो गए और दरवाजे खुलना मुश्किल हो गया,इसके बाद वाहनों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप सामने आया है, यदि जांच में यह तथ्य सही साबित होते हैं तो यह किसी क्षणिक आवेश में हुई घटना नहीं बल्कि पूर्व नियोजित सामूहिक हत्या का मामला होगा।

लाला सिंह की दर्दनाक मौत

घटना का सबसे हृदयविदारक दृश्य भारत सिंह उर्फ लाला सिंह की मौत को लेकर सामने आया,बताया जाता है कि वाहन का जिस हिस्से में वे बैठे थे,उसी ओर का दरवाजा पूरी तरह जाम हो गया था, आग की लपटें भी उसी दिशा से तेजी से फैलीं, परिणाम यह हुआ कि वे वाहन से बाहर नहीं निकल सके और वहीं जिंदा जल गए,अन्य लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुए,लेकिन तब तक वे गंभीर रूप से झुलस चुके थे,बाद में नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया,इस प्रकार एक ही वाहन में बैठे चार लोगों में से तीन की जान चली गई, योगेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल अवस्था में जीवित बच गए।

योगेंद्र सिंह और मयंक सिंह जांच की दो अहम कड़ियां

पूरे मामले में योगेंद्र सिंह का जीवित बचना जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है,वे उसी वाहन में मौजूद थे जिसमें तीन लोगों की मौत हुई,इसलिए उनका बयान पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, दूसरी ओर मयंक सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जाता है कि उनके साथ भी बर्बर मारपीट की गई, यदि दोनों पक्षों से जुड़े जीवित बचे लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर बयान देते हैं तो जांच को नई दिशा मिल सकती है।

दुर्घटना या हत्या?

घटना के बाद प्रारंभिक स्तर पर बिजली के तार टूटने से आग लगने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन बाद में यह तर्क कमजोर पड़ता गया, तकनीकी जानकारों का कहना है कि सामान्य बिजली के तार टूटने से इतनी भीषण आग लगना और कई लोगों का वाहन सहित जल जाना असामान्य है,इसी कारण अब जांच एजेंसियां आग लगने के वास्तविक कारणों की फोरेंसिक जांच कर रही हैं।

सरगुजा आईजी की निगरानी में जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी स्वयं पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं,घटनास्थल को सील कर दिया गया है,फोरेंसिक टीमों ने निरीक्षण किया है, पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है,कई संदिग्धों से पूछताछ और कुछ गिरफ्तारियों की जानकारी भी सामने आई है,लेकिन पुलिस अभी खुलकर जानकारी देने से बच रही है,पुलिस का मानना है कि जल्दबाजी में खुलासा करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

कोरिया के विकास को मिलेगी नई रफ्तार,

पीडब्ल्यूडी सचिव ने की सड़कों और पुल परियोजनाओं की समीक्षा

- विधायक भैयालाल राजवाड़े और कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने रखे जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्ताव
- सड़क चौड़ीकरण, पुल निर्माण और बायपास परियोजनाओं पर बनी सहमति
- हजारों ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में अधोसंरचना विकास को गति देने के उद्देश्य से गुरुवार को बैकुंठपुर स्थित सर्किट हाउस में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े,कलेक्टर रोक्तिमा यादव,लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी सहित लोक निर्माण एवं सेतु विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे,बैठक में जिले की प्रमुख सड़क एवं पुल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए विकास कार्यों को शीघ्र स्वीकृति और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

खरवत चौक से जमगहना तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क को मिली प्राथमिकता-समीक्षा बैठक में कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने वर्ष 2026-27 की प्राथमिकता सूची के अंतर्गत खरवत चौक (एनएच-43) से गेज नदी पुल होते हुए जमगहना मुख्य मार्ग तक लगभग 13 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना का प्रस्ताव रखा, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 9,648.27 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया, कलेक्टर ने बताया कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था मजबूत होगी तथा जिले के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

बैकुंठपुर-चोटिया मार्ग सहित ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर भी हुई चर्चा...

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने वर्ष 2025-26 की प्राथमिकता सूची में शामिल बैकुंठपुर से चोटिया मार्ग के दो लेन एवं पेव शोल्डर निर्माण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया,इसके अलावा दुधनियाकला क्षेत्र में दिनेश किराना दुकान से संतोषी मंदिर एवं थाडपाथर देव स्थल तक लगभग तीन किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता देने की मांग की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना में बैकुंठपुर-भैयाथान-प्रतापपुर-बलरामपुर मार्ग शामिल करने का प्रस्ताव

बैठक में वर्ष 2026-27 की द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत बैकुंठपुर-भैयाथान-प्रतापपुर-बलरामपुर मार्ग के निर्माण,उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य का प्रस्ताव भी रखा गया,अधिकारियों का मानना है कि यह मार्ग क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार, परिवहन और पर्यटन गतिविधियों को भी गति प्रदान करेगा।

गेज नदी पर दो बड़े पुलों के निर्माण से हजारों लोगों को मिलेगा लाभ

समीक्षा बैठक में जिले की महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं पर विशेष फोकस रहा,कलेक्टर ने जानकारी दी कि खंधौरा से सोस मार्ग पर गेज नदी में 773.30 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित उच्चस्तरीय पुल के निर्माण से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो जाएगी, इस परियोजना से 11 गांवों के करीब 12 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षभर सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा,इसी प्रकार सोस से चिरमी मार्ग पर गेज नदी में 650 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य से सात गांवों के लगभग 12 हजार ग्रामीण लाभान्वित होंगे। इस पुल के बनने से जिला मुख्यालय की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी।

दसेर नदी पर प्रस्तावित पुल से सात गांवों को मिलेगा सीधा लाभ...

आनंदपुर-दसेर मार्ग पर दसेर नदी में 850 लाख रुपये की लागत से पुल निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया,कलेक्टर ने बताया कि इस पुल के निर्माण से दसेर ग्राम सहित आसपास के सात गांवों के दो हजार से अधिक ग्रामीणों को वर्षभर बेहतर आवागमन सुविधा प्राप्त होगी, बरसात के दौरान संपर्क बाधित होने की समस्या से भी लोगों को राहत मिलेगी।

बिशुनपुर-सलका-बैकुंठपुर बायपास मार्ग के लिए मांगी गई स्वीकृति

बैठक में वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में शामिल बिशुनपुर से सलका-बैकुंठपुर बायपास मार्ग निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई, लगभग 7.70 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण हेतु पुल-पुलिया सहित 700 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है,परियोजना के लिए 2,284.07 लाख रुपये का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया है,जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए सचिव से अनुरोध किया गया।

जनहित में...

प्रमुख प्रस्ताव एक नजर में...

- खरवत चौक से जमगहना तक 13 किमी फोरलेन सड़क – 96.48 करोड़
- बिशुनपुर-सलका-बैकुंठपुर बायपास मार्ग – 7.70 किमी
- बैकुंठपुर-चोटिया दो लेन सड़क निर्माण
- दुधनियाकला में 3 किमी ग्रामीण सड़क निर्माण
- खंधौरा-सोस मार्ग पर गेज नदी में उच्चस्तरीय पुल – 7.73 करोड़
- सोस-चिरमी मार्ग पर गेज नदी में पुल – 6.50 करोड़
- आनंदपुर-दसेर मार्ग पर दसेर नदी में पुल – 8.50 करोड़
- सोनहत में नए सर्किट हाउस निर्माण का प्रस्ताव

सोनहत में सुसज्जित सर्किट हाउस निर्माण की मांग...

बैठक के दौरान कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने सोनहत विकासखंड मुख्यालय में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एक आधुनिक एवं सुसज्जित सर्किट हाउस निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया,उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियों और अधिकारियों के आवागमन को देखते हुए सर्किट हाउस की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

विधायक भैयालाल राजवाड़े ने बताया जनता की वर्षों पुरानी मांग...

बैठक में विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण जिलेवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, इन परियोजनाओं के पूरा होने से आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी,उन्होंने कहा कि सड़क और पुल निर्माण केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास, शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार से भी सीधे जुड़ा हुआ विषय है।

सचिव ने अधिकारियों को दिया गुणवत्ता और समय-सीमा के निर्देश

समीक्षा बैठक के अंत में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विधायक एवं कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करते हुए एकीकृत प्राक्कलन तैयार किया जाए ताकि निविदा प्रक्रिया समय पर प्रारंभ हो सके,सचिव ने लोक निर्माण एवं सेतु विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने,फील्ड स्तर पर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने तथा सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा और मानकों के अनुरूप पूरा कराने के निर्देश दिया।

योग दिवस पर बैकुण्ठपुर में होगा भव्य सामूहिक योगाभ्यास

प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम होंगे मुख्य अतिथि,'स्वस्थ आयु के लिए योग' थीम पर होगा आयोजन

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर स्थित मानस भवन में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा,प्रातः 7 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे,आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों-कर्मचारियों,सामाजिक संगठनों,युवाओं, महिलाओं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

'स्वस्थ आयु के लिए योग' है इस वर्ष की थीम

जिला आयुष अधिकारी डॉ. एल्विना ग्रेस टोप्पो ने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' निर्धारित की गई है,आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा,उन्होंने बताया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित एवं सकारात्मक जीवनशैली का आधार है। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है तथा व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है।

योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं-कलेक्टर

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिलेवासियों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है, उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मूल आधार है और इसे केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति का शारीरिक,मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य मजबूत होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जीवनशैली संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए योग सबसे प्रभावी और सरल उपायों में से एक है, कलेक्टर ने नागरिकों से स्वयं योग अपनाने के साथ-साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।

कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार होगा सामूहिक योगाभ्यास

डॉ. एल्विना ग्रेस टोप्पो ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को योग के महत्व, उसकी उपयोगिता तथा स्वास्थ्य संबंधी लाभों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी,इसके साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा,कार्यक्रम में विभिन्न योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान संबंधी गतिविधियां शामिल रहेंगी।

योग संगम पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

आयुष विभाग ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा 'योग संगम पोर्टल-2026' प्रारंभ किया गया है,इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं,ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को अपने योग दिवस कार्यक्रमों का पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है,कार्यक्रम संपन्न होने के बाद आयोजन का विवरण एवं फोटोग्राफ भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, इससे देशभर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों का समेकित दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा।

व्हाट्सऐप के माध्यम से भी मिलेगी योग प्रशिक्षण सामग्री

आयुष विभाग ने बताया कि इच्छुक नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क योग प्रशिक्षण सामग्री,वीडियो तथा योग सत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक योग को पहुंचाना तथा उन्हें नियमित योगाभ्यास के लिए प्रेरित करना है।

संस्थाओं से अधिकाधिक सहभागिता की अपील

जिला आयुष विभाग ने सभी शासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, नगरीय निकायों,ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं से अधिकाधिक संख्या में योग संगम पोर्टल पर पंजीयन कराने और योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करने की अपील की है, विभाग का मानना है कि सामूहिक सहभागिता से योग को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान को और मजबूती मिलेगी।

छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण

जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में योगाभ्यास प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा चिन्हित योग प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी, जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा नामित योग प्रशिक्षक डॉ. रमाकांत कुर्रे एवं अनिल शर्मा प्रतिभागियों को योगाभ्यास का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, उनके मार्गदर्शन में उपस्थित लोग योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास करेंगे।

कार्यक्रम एक नजर में...

आयोजन : 12 वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तिथि : 21 जून 2026
समयः प्रातः 7 बजे
स्थान : मानस भवन, बैकुण्ठपुर
मुख्य अतिथि : प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम
थीम : 'स्वस्थ आयु के लिए योग'
विशेष आकर्षण : सामूहिक योगाभ्यास,योग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन एवं कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन।

जमीन विवाद में खून से लाल हुए रिश्ते,सूरजपुर में भतीजों पर चाचा की दिनदहाड़े हत्या का आरोप

न्यायालय से लौट रहे थे बरन राम,रास्ते में रोककर किया गया हमला

-संवाददाता-

सूरजपुर,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिले में गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। पतरापारा रोड स्थित लवलीहुड कॉलेज के पास जमीन विवाद को लेकर भतीजों द्वारा अपने ही चाचा की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, घटना दिनदहाड़े हुई,जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई, मृतक की पहचान ग्राम पीढ़ा निवासी बरन राम के रूप में हुई है, जानकारी के अनुसार वह किसी न्यायिक कार्य से सूरजपुर न्यायालय आए हुए थे और दोपहर करीब 2:30 बजे अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार योग्यता राजवाड़े उम्र 25 वर्ष रोहित राजवाड़े उम्र 22 वर्ष अनुसार बरन राम और उनके परिजनों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि खून के रिश्ते ही एक-दूसरे के दुश्मन बन गए, स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था, न्यायालय में भी इसी संबंध में मामला चलने की चर्चा है,गुरुवार को न्यायालय से लौटते समय बरन राम पर हमला किए जाने से यह आशंका और मजबूत हो गई है कि हत्या का संबंध जमीन विवाद से ही जुड़ा हो सकता है।

धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला,मौके पर मौत...

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बरन राम को रास्ते में रोककर उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया,हमला इतना अचानक और गंभीर था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला,शरीर पर कई गंभीर चोटें आने के कारण उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया,दिनदहाड़े हुई इस वारदात से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई,घटना के बाद आरोपी मौके से भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने दोनों संदिग्धों को लिया हिरासत में...

घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पुलिस अधिकारियों के

अनुसार मामले में दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है,प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे जमीन संबंधी विवाद सामने आया है,हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।

रिश्तों पर भारी पड़ रही जमीन की लड़ाई

सूरजपुर की यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि जमीन और संपत्ति के विवाद किस तरह परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं,जिस चाचा ने कभी अपने भतीजों को परिवार का हिस्सा मानकर स्नेह दिया होगा,आज उसी पर जानलेवा हमला करने के आरोप लग रहे हैं,यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि टूटते पारिवारिक रिश्तों और बढ़ती सामाजिक कटुता की भी कहानी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है,लोग चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

CMYK

सक्ती में 1.44 करोड़ का गांजा जब्त

नाबालिग समेत दो गिरफ्तार,राजस्थान में होनी थी गांजा की सप्लाई

सक्ती, 18 जून 2026। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में गुरुवार को पुलिस ने ट्रेलर से करीब 1 करोड़ 44 लाख 48 हजार 250 रुपए गांजा बरामद किया है। ट्रेलर में 8 प्लास्टिक बोरियों में छिपाकर रखे गए कुल 40 पैकेटों में 208.965 किलोग्राम गांजा रखा गया था। गांजा को ओडिशा से लोडकर छत्तीसगढ़ के रास्ते राजस्थान ले जाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डभरा सुमीत गुप्ता के मार्गदर्शन में चौकी फगुरम और थाना डभरा पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। चौकी फगुरम प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली के नेतृत्व में पुलिस टीम को 17 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा भरकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल रणनीति बनाते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन कर ग्राम बोडासागर स्थित सागर फैमिली ढाबा के सामने खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध टाटा सिगना ट्रेलर क्रमांक आरजे09जीसी 5216 को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रेलर में

रखी 8 प्लास्टिक बोरियों से कुल 40 पैकेट गांजा बरामद किया गया। प्रत्येक पैकेट का वजन लगभग 5 किलोग्राम था। जब्त गांजा का कुल वजन 208.965 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 44 लाख 48 हजार 250 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेलर को भी जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा ट्रेलर में भरा फ्लोर्सपार पाउडर, जिसकी कीमत 21 लाख 42 हजार 210 रुपये है, तथा आरोपियों के कब्जे से मिले वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री का कुल मूल्य 1 करोड़ 66 लाख 20 हजार 460 रुपये आंका गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जिले के थाना जेवाजा क्षेत्र निवासी अर्पित सिंह (20 वर्ष), पिता रमेश सिंह तथा उसके साथ मौजूद एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 219/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

राजस्थान का आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई के बाद पुलिस ने ट्रेलर में सवार लोगों से गांजा परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके। पूछताछ में भी उनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जिले के जेवाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले अर्पित सिंह (20) को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ मौजूद एक नाबालिग को भी मामले में पकड़ा गया।दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध दर्ज किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की यह बड़ी खेप किसके लिए भेजी जा रही थी और इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल...

छत्तीसगढ़ में 7 आईएफएस अधिकारियों के तबादले

रायपुर, 18 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के तबादले और नई पद स्थापनाओं का आदेश जारी किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए इस फेरबदल में 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी आदेश के मुताबिक मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) कांकेर राजेश कुमार चंदेल को मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर आलोक कुमार तिवारी को मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/आईटी) बनाया गया है। मुख्य वन संरक्षक,कार्य योजना बिलासपुर राम अवतार दुबे को क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, नया रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वन संरक्षक (प्रशासन, राजभाषा एवं समन्वय) विवेकानंद झा को प्रभारी मुख्य

वन संरक्षक (प्रादेशिक) कांकेर बनाया गया है। वहीं वन उप संरक्षक (रिकॉर्ड) लक्ष्मण सिंह को प्रभारी वन संरक्षक, कार्य योजना मंडल बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। वन्यजीव क्षेत्र में कार्यरत स्टायलो मंगावी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा वर्ष 2021 बैच की आईएफएस अधिकारी निमला खेस्स को जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। वन विभाग ने एक और आदेश जारी किया है,जिसमें अनिमेष गोवर्धन (रा.व.से.),संपदा अधिकारी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी वन उप संरक्षक (रोकड) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन वल प्रमुख, अरण्य भवन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति,भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सीएम साय अचानक सभी मंत्रियों को रात 9 बजे सीएम हाउस बुलाया

ढाई साल के कामों की समीक्षा,विभागों से लिए सुझाव,सत्ता-संगठन में तालमेल पर चर्चा

रायपुर, 18 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अचानक सभी मंत्रियों को रात 9 बजे सीएम हाउस बुलाया। अचानक मिले बुलावे से कई मंत्री अपने कार्यक्रम रद्द कर रायपुर पहुंचे। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं होती रहीं,लेकिन इसे केवल राजनीतिक अटकलें बताया गया। जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की समीक्षा की गई और आगामी ढाई साल की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। विभिन्न विभागों से सुझाव लिए गए। साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री केदार कश्यप, गुरु खुशवंत साहेब, लक्ष्मी राजवाड़े,दयाल दास बघेल सहित कई मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री अरुण साव,विजय शर्मा,मंत्री टंकराम वर्मा, लखन लाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल भी बैठक में पहुंचे। दरअसल,पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा चल रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री की इस अचानक बुलाई गई बैठक को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्री दिनभर अपने प्रभार वाले जिलों और सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन देर शाम उन्हें तत्काल रायपुर पहुंचने के निर्देश मिले। निर्देश मिलते ही मंत्री राजेश अग्रवाल सरगुजा से रायपुर पहुंचे। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी में आयोजित कार्यक्रम को बीच में छोड़कर रायपुर पहुंचे।

लोकभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आत्मीय स्वागत

रायपुर, 18 जून 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को एकदिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन

साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री केदार कश्यप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद ओम बिरला सीधे लोकभवन पहुंचे जहां राज्यपाल रमेन डेका ने लोकसभा अध्यक्ष का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे।

21 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी

जिलाध्यक्षों को देंगे टारगेट शीट,मंत्री बोले...प्रियंका के लिए गुलाब बिछाए,राहुल के पैर दारू से धोएं

रायपुर, 18 जून 2026। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे,जहां वे हाल ही में नियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में टारगेट शीट और टिप्स देंगे। अभनपुर में 20 से 29 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एक्टिव कार्यकर्ताओं को वे कई जिम्मेदारियां भी देंगे। इससे पहले राहुल गांधी सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे। करीब 3 साल बाद फिर उनके दौरे को लेकर सियासत हो रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि,कांग्रेस ने बहुत शराब घोटाला किया है। इसलिए अपने आका को खुश करने कांग्रेसी उनका पैर शराब से धोकर स्वागत करें। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। उन्हें एक-दो बार छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए, ताकि यहां कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो सके।

9 दिन तक कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण : राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के

संगठनात्मक अभियान से जुड़ा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अभनपुर में आयोजित होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि, प्रदेश कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में 20 से 29 जून के बीच एक बड़े प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है।

ओडिशा के जिलाध्यक्ष भी होंगे शामिल : शिविर में छत्तीसगढ़ के 41 जिलाध्यक्षों साथ ओडिशा के जिलाध्यक्षों को भी शामिल किए जाने की प्लानिंग है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा गया है और अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।

सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देगी कांग्रेस : यह पूरा आयोजन कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी 2025-26 में जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अभियान के तहत जिला,ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। पार्टी का फोकस सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने और संगठन में जवाबदेही तय करने पर है।

जानकारी के मुताबिक,इस ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश,सुप्रिया श्रीनेत,पवन खेड़ा, शशिकांत सेंथिल सहित तमाम दिग्गज नेता और एक्सपर्ट भी शामिल हो सकते हैं।

नारायणपुर के जंगल में सुरक्षा बलों ने गोला-बारूद का बड़ा जखीरा किया बरामद

नारायणपुर, 18 जून 2026। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर जिले के मसपुर-गुडरापाल जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने नक्सलियों के छिपाए गए हथियारों और गोला-बारूद के बड़े जखीरे का पता लगाते हुए उसे जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस और बीएसएफ की 133वीं वाहिनी की 'ई' कंपनी द्वारा कैंप मसपुर के आसपास के जंगलों में विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जवानों की नजर जंगल के भीतर एक संदिग्ध स्थान पर पड़ी। इलाके की घेराबंदी कर जब तलाशी ली गई तो वहां से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई। बरामद सामग्री में एक देसी बीजीएल लॉन्चर, सात बीजीएल गन, एक 12 बोर राइफल और 37 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा 15 मीटर वायर

और पांच पोच भी जब्त किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन हथियारों को नक्सलियों ने भविष्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जंगल में छिपाकर रखा था। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह सामग्री काफी समय पहले जंगल में छिपाई गई थी।

रील का जुनून बना मौत की वजह मोबाइल कैमरे में कैद हुआ नवविवाहिता का आखिरी पल

रायगढ़, 18 जून 2026। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की चाहत ने रायगढ़ में एक नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली। कोष्टापारा नया गंज मोहल्ले में 22 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के वक्त महिला मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और पूरा घटनाक्रम उसके कैमरे में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतका की हाल ही में शादी हुई थी और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहती थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह किसी नाटकीय सीन की रील शूट कर रही थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जान ले ली। जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो महिला सीलिंग फैन से लटकी मिली,जिसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जांच के दौरान मृतका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि फोन में रिकॉर्ड वीडियो घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझने में अहम सबूत साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाएंगे

रायपुर, 18 जून 2026। छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने की। बैठक में समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य में संचालित शराब व्यसन मुक्ति अभियान की प्रगति, नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, नशामुक्ति केन्द्रों के संचालन तथा भविष्य की कार्ययोजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य स्तरीय समिति की पूर्व बैठक 6 अक्टूबर 2023 के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड की एक हजार से अधिक जनसंख्या वाली नवीन ग्राम पंचायतों में भारत

माता वाहिनी के गठन एवं विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे नशामुक्ति अभियान को ग्रामीण स्तर तक और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समिति ने नशापीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों की क्षमता 15 से बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया । केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में ऐसे केन्द्र संचालित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत राज्य के 5 जिलों में नए नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने की दिशा में भी पहल की जाएगी। 5 नये नशामुक्ति केंद्र मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, बेमेतरा, कोरबा जिलों में खोले जायेंगे। बैठक में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। समिति का मानना है कि इससे केन्द्रों की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी। इस अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान अभियान अंतर्गत किए गए कार्यों तथा व्यय की समीक्षा भी की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मानवता को शांति,आत्मसंयम,करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं भगवान महावीर के विचार : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

अहिंसा,करुणा,सत्य और आत्मसंयम के संदेश की आज पूरे विश्व को आवश्यकता : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 18 जून 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव में शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने जैन मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो रहे पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आचार्य पद केवल एक पद नहीं,बल्कि तप,त्याग,ज्ञान और समाज को दिशा देने वाली साधना का सर्वोच्च प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी मानवता को शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। वर्तमान समय में जब विश्व तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, तब जैन दर्शन की शिक्षाएं और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। बिरला ने कहा कि पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज का आचार्य पदारोहण संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव का क्षण है। वहीं शतावधानी हंसभद्र मुनि जी महाराज ने अपनी विलक्षण स्मरणशक्ति, ज्ञान और साधना के बल पर देशभर में विशेष पहचान बनाई है। उनके तप और साधना से

समाज को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि भौतिक संसाधन केवल सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं,लेकिन जीवन का वास्तविक सुख आत्मनियंत्रण,आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना से प्राप्त होता है। जैन संतों का तपस्वी जीवन समाज को प्रेरणा देता है और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने सभी जैन संतों,साध्वियों और श्रद्धालुओं को नमन करते हुए महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहली बार आयोजित हो रहा यह आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा,साधना और संस्कृति का यह विराट आयोजन पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर बन गया है। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए संत-साध्वियों,श्रद्धालुओं एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ धन्य हुआ है और इस आयोजन से पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज का आचार्य पद पर पदारोहण उनके ज्ञान,तप,संयम,साधना और समाज के प्रति समर्पित जीवन का सम्मान है। उन्होंने 14 वर्षीय बाल मुनि शतावधानी हंसभद्रमुनि जी महाराज को भी नमन करते हुए कहा कि इतनी कम आयु में उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति, एकाग्रता और ज्ञान-साधना सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है। एक साथ हजार प्रश्नों को स्मरण रखना और उनका क्रमवार उत्तर देना असाधारण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रायपुर का यह इंडोर स्टेडियम ज्ञान,साधना और अध्यात्म का तीर्थस्थल प्रतीत हो रहा है। जैन संतों ने सदैव अहिंसा,करुणा,सत्य और आत्मसंयम का संदेश दिया है,जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। भगवान महावीर स्वामी का 'जियो और जीने दो' का संदेश वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति,सद्भाव और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि है तथा राज्य सरकार सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जैन मुनिगण कठिन तप, उपवास और संयम के माध्यम से समाज को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लंबी पदयात्रा और तपस्या के बाद रायपुर पहुंचे साधु-संतों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इतने बड़े आध्यात्मिक आयोजन में देशभर के संत-साध्वी और श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैन संतों का त्याग,तपस्या और अनुशासित जीवन समाज को सदैव प्रेरित करता है।विनयकुशल मुनि जी के आचार्य पदारोहण का यह आयोजन लोगों को अध्यात्म और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा। कार्यक्रम में सकल जैन श्रीसंघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल,विजय बघेल,श्रीमती कमलेश जांगड़े, महेश कश्यप, विधायक राजेश मूणत सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

घटनास्थल पर आरोपियों से पूछताछ, 4 गिरफ्तार

3 फरार, धारा 163 लागू...खनिज विभाग और प्रशासन की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

नौगई से बैकुंठपुर तक पसरा सन्नाटा, फरार आरोपियों की तलाश में युद्धस्तर पर पुलिस कार्रवाई, खनिज विभाग और प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे गंभीर सवाल

- रेत माफिया की जंग या प्रशासनिक नाकामी ? कोरिया तिहरा हत्याकांड ने खड़े किए बड़े सवाल...
- तीन मौतें,एक जलती फॉर्च्यूनर और कई राज : कोरिया के 'लाल रेत कांड' की परतें खुलनी बाकी...
- जब रेत से ज्यादा कीमती हो गया वर्चस्व : नौगई में तीन जानें गईं, प्रशासन देखता रह गया!
- कोरिया का 'लाल रेत कांड' : तीन हत्याओं से दहला जिला,फरार आरोपियों की तलाश में युद्धस्तर पर कार्रवाई

रवि सिंह

कोरिया/सोनहत,18 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड स्थित ग्राम नौगई में घटित तिहरे हत्याकांड ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है,भाजपा नेता एवं व्यवसायी लल्ला सिंह उर्फ भरत सिंह समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पूरा क्षेत्र तनाव,भय और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है,एक तरफ पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दिन-रात जुटी हुई है,तो दूसरी तरफ आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या यह केवल दो गुटों का विवाद था या फिर रेत कारोबार के उस समानांतर साम्राज्य का परिणाम,जिसकी जानकारी प्रशासन और खनिज विभाग को पहले से थी लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई? नौगई में हुई इस वारदात ने सिर्फ तीन लोगों की जान नहीं ली,बल्कि सुशासन, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़े प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। जिस तरह दिनदहाड़े नहीं तो खुलेआम रास्ते में घेरकर हमला किया गया,वाहन को आग के हवाले कर दिया गया और तीन लोगों की मौत हो गई,उससे साफ संकेत मिलता है कि विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ था बल्कि इसके पीछे लंबे समय से सुलग रही प्रतिद्वंद्विता थी।

शांत वनांचल में खून और आग का तांडव...

सोनहत क्षेत्र लंबे समय से अपने प्राकृतिक संसाधनों और रेत खदानों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रेत कारोबार को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, प्रभाव और आर्थिक हितों ने कई बार विवादों को जन्म दिया है, नौगई में हुई यह घटना उसी संघर्ष का सबसे भयावह रूप मानी जा रही है,प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने आ रही जानकारियों के अनुसार घटना के दौरान ऐसा हिंसक टकराव हुआ जिसमें लल्ला सिंह उर्फ भरत सिंह सहित तीन लोगों की जान चली गई,घटना के बाद जिस प्रकार फॉर्च्यूनर वाहन जलता हुआ मिला,उसने पूरे प्रदेश का ध्यान इस मामले की ओर खींच लिया, घटनास्थल के दृश्य इतने भयावह बताए जा रहे हैं कि वहां मौजूद लोग आज भी उस मंजर को याद कर सिहर उठते हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने पहले कभी इस प्रकार की हिंसक घटना नहीं देखी थी।

फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस का बड़ा अभियान...

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा और एडिशनल एसपी सुरेशा चौबे स्वयं पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं,पुलिस ने इस मामले में कुल सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, इनमें से चार आरोपियों अक्षय त्रिपाठी,विशाल त्रिपाठी,सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मुन्नू त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि तीन आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, सूत्रों के अनुसार फरार आरोपियों के मोबाइल फोन बंद हैं और वे लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं,पुलिस साइबर सेल की मदद से उनकी अंतिम लोकेशन,कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है,कई जिलों में दबिश दी जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा,हत्या,हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है,जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या घटना में और लोग भी शामिल थे या नहीं।

घटनास्थल पर ले जाकर कराई गई पूछताछ...

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को नौगई स्थित घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ की है,इस प्रक्रिया का उद्देश्य वारदात के क्रम को समझना और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का मिलान करना था,सूत्रों के अनुसार आरोपियों से यह पूछा गया कि हमले की शुरुआत कैसे हुई, किसने किस पर हमला किया,कौन-कौन मौके पर मौजूद था और वाहन में आग कैसे लगी, बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल पर पूरे घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया,जांच अधिकारी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमले की पूर्व योजना बनाई गई थी या विवाद अचानक हिंसक हो गया, घटनास्थल पर पूछताछ के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।

खौफ ऐसा कि कोई बोलने को तैयार नहीं-घटना के बाद नौगई और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है, लोग बातचीत तो कर रहे हैं,लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार की हिंसा हुई है,उससे हर व्यक्ति भयभीत है,कई लोग यह मान रहे हैं कि मामला अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और आगे भी तनाव बना रह सकता है,चश्मदीदों की चुप्पी भी जांच के लिए चुनौती बन रही है। पुलिस को उम्मीद है कि समय के साथ लोग आगे आएंगे और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य साझा करेंगे, गांव में पसरा सन्नाटा इस बात का संकेत है कि लोग अभी भी सदमे में हैं। हर घर में इस घटना की चर्चा है,लेकिन खुलकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं।

फरार आरोपी खुलवा सकते हैं कई बड़े राज...

जांच से जुड़े सूत्रों का मानना है कि इस मामले की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है,पुलिस को उम्मीद है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी, यह भी जांच का विषय है कि क्या इस विवाद के पीछे केवल व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी या फिर रेत कारोबार से जुड़े आर्थिक हितों का बड़ा टकराव था,स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं जो सीधे तौर पर सामने नहीं आए हैं लेकिन पर्दे के पीछे से सक्रिय थे। पुलिस अभी इस दिशा में भी जानकारी जुटा रही है।

सियासत में भी मचा भूचाल

यह मामला अब केवल आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, आरोपी पक्ष को स्थानीय क्षेत्रीय विधायक का करीबी बताया जा रहा है, हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना के बाद विधायक की चुप्पी राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी हुई है,वहीं बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े लगातार इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं,उनके बयानों ने प्रशासन पर दबाव बढ़ाया है और राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है,सियासी विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच में किसी प्रकार के राजनीतिक संरक्षण या प्रभाव के संकेत मिलते हैं तो मामला और अधिक गंभीर हो सकता है।

धारा 163 लागू...संवेदनशील क्षेत्र बने सुरक्षा छावनी

घटना के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं,कलेक्टर रोक्तिमा यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार महलपारा बैकुंठपुर,नौगई गांव तथा कटगोड़ी स्थित क्रेशर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है, इन क्षेत्रों के 300 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की सभा,धरना, प्रदर्शन अथवा जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है,हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री के प्रसार पर भी निगरानी रखी जा रही है, प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

सबसे बड़ा सवाल : क्या प्रशासन पहले से जानता था?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न प्रशासनिक भूमिका को लेकर उठ रहा है, स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से यह चर्चा रही है कि रेत कारोबार को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ था। यदि ऐसा था तो संबंधित विभागों ने समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? कहा जा रहा है कि दो दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद थाने तक पहुंचा था,यदि यह तथ्य जांच में सही पाया जाता है तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि आखिर उस समय प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या पुलिस को संभावित हिंसा की आशंका नहीं थी? क्या खनिज विभाग को क्षेत्र में चल रहे विवादों की जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं।

खनिज विभाग की भूमिका पर उठ रही उंगलियां...

इस तिहरे हत्याकांड के बाद सबसे ज्यादा आलोचना खनिज विभाग की हो रही है,स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत कारोबार को लेकर लंबे समय से कई प्रकार की शिकायतें सामने आती रही हैं,लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई,यदि क्षेत्र में अवैध वसूली,दबाव और वर्चस्व की लड़ाई जैसी गतिविधियां चल रही थीं तो विभाग ने उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए? जनता पूछ रही है कि क्या संबंधित अधिकारियों को वास्तव में कुछ पता नहीं था या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली गई थीं? इसी वजह से अब यह हत्याकांड केवल अपराध की घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है।

जलती फॉर्च्यूनर और सुशासन पर उठते सवाल...

नौगई में जलती हुई फॉर्च्यूनर की तस्वीरें पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, यह केवल एक वाहन नहीं था,बल्कि उस व्यवस्था का प्रतीक बन गया है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, जब तीन लोगों की जान चली जाए,गांव दहशत में डूब जाए,पुलिस को संभागभर की फोर्स लगानी पड़े और प्रशासन को धारा 163 लागू करनी पड़े,तब यह मान लेना कठिन हो जाता है कि सब कुछ सामान्य था,यह घटना बता रही है कि यदि छोटे विवादों को समय रहते नहीं रोका गया तो वे किस प्रकार बड़े रक्तपात में बदल सकते हैं।

अब पूरी नजर जांच पर...

फिलहाल पूरे जिले की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं,लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस खूनी संघर्ष की असली वजह क्या थी,किसने क्या भूमिका निभाई और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था,फरार आरोपियों की गिरफ्तारी,कॉल डिटेल रिकॉर्ड,डिजिटल साक्ष्य, घटनास्थल से मिले प्रमाण और पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि नौगई का यह तिहरा हत्याकांड कोरिया जिले के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तीन मौतों, जलती फॉर्च्यूनर और रेत कारोबार के खूनी संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि जब प्रशासनिक निगरानी कमजोर पड़ती है और विवादों को समय रहते नहीं सुलझाया जाता,तब उसका परिणाम केवल कानून-व्यवस्था का संकट नहीं बल्कि मानव जीवन की अपूरणीय क्षति के रूप में सामने आता है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)